E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 299 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 5 जून, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास और विजन 2047 पर की चर्चा पेज 2
असम भाजपा विश्व पर्यावरण दिवस को एक विशाल पौधरोपण अभियान... पेज 3
देश के लिए रोल मॉडल बना यूपी का पंचायती राज विभाग, 3 अभिनव... पेज 5
बीसीसीआई बैठक में होगा सूर्यकुमार की कप्तानी पर फैसला, वैभव को ... पेज 7

सुप्रभात

गरिब वह है, जिसका खर्च आमदनी से ज्यादा है।

-बुएयर

न्यूज गैलरी

अहमदाबाद मे गंदा पानी पीने से 500 लोग बीमार

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के सोला इलाके में कल आकांक्षा अपार्टमेंट में गंदा पानी पीने से स्थानीय लोगों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नर्मदा के पीने के पानी में सीवेज का पानी मिलने से लोगों को डायरिया, उल्टी और पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। कई बार बताने के -शेष पृष्ठ छह पर

राज्य में आज होगा कैबिनेट विस्तार

12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ तीन नए चेहरों को भी मिलेगी जगह

गुवाहाटी। असम में शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। 12 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनमें तीन नए चेहरे भी शामिल होंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से की गई, जहां उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को दोपहर 12:45 बजे आयोजित किया जाएगा। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि असम विधानसभा के निम्नलिखित माननीय सदस्य 5 जून 2026 को दोपहर 12:45 बजे असम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। असम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों में अश्विनी रे सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, विश्वजीत दैमारी, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, केशब महंत, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पिजुष हजारिका, रनोज पेगु और सुशांत बरगोहाईं शामिल हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, नामित मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा। यह समारोह 5 जून को दोपहर 12:45 बजे गुवाहाटी के ज्योति-बिष्णु अंतरजातिक कला मंदिर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद असम में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन में मंत्रिमंडल विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रियों की नियुक्ति से विभागों के आवंटन और सरकार के पूर्ण प्रशासनिक -शेष पृष्ठ छह पर

ममता ही रहेंगी सुप्रीम लीडर, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में भी बगावत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी के बागी खेमे में महज 24 घंटे के भीतर ही असंतोष के सुर उभर आए हैं। 58 बागी विधायकों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक दल पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस बागी गुट में भारी बेचैनी देखी जा रही है। कई विधायकों ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी ही उनकी सुप्रीम लीडर रहेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ममता बनर्जी को महज एक सलाहकार बनाकर छोड़ा गया, तो वे इस बागी गुट में रहने पर दोबारा विचार कर सकते हैं। बागी विधायक दल के नवनिर्वाचित विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद ही बागी गुट के भीतर अलग-अलग सुर दिखाई देने लगे। इससे साफ है कि बागियों के सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे एक तरफ पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, वे टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी के साथ अपना राजनीतिक और भावनात्मक रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं। बैठक खत्म होने के बाद पांचला के बागी विधायक गुलशन मल्लिक ने पत्रकारों से खुलकर -शेष पृष्ठ छह पर

रास चुनाव भाजपा ने घोषित किए 11 उम्मीदवार

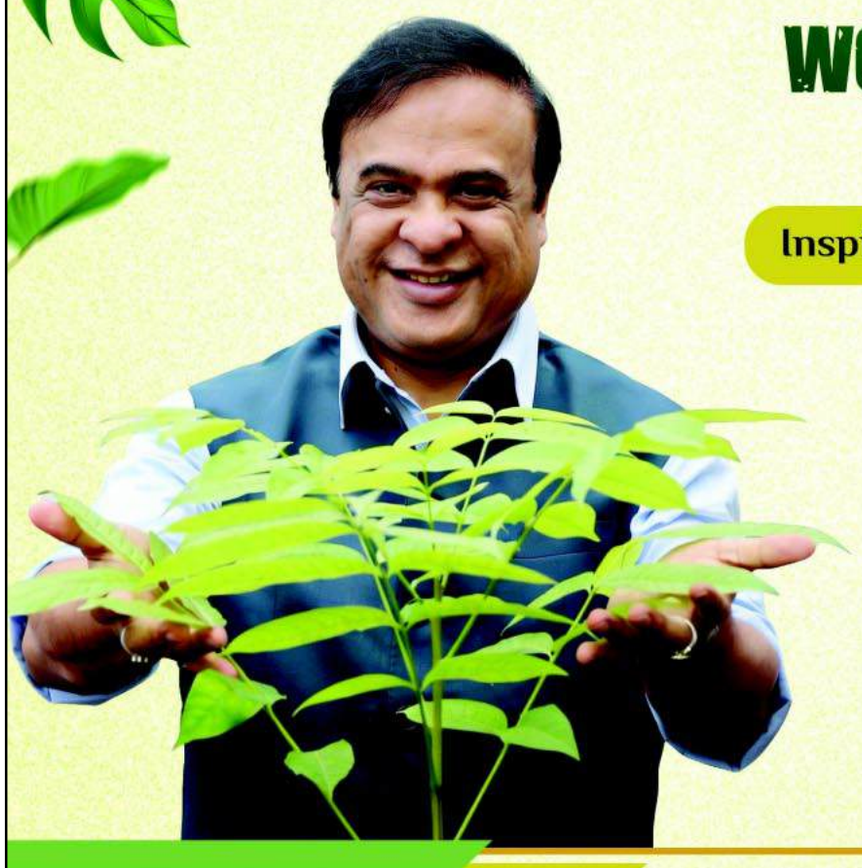

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को बड़ा मौका देते हुए मैदान में उतारा है। उनके साथ रजनीश अग्रवाल को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान में पार्टी ने इस बार केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट देने से इनकार कर दिया है। उनकी जगह डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर -शेष पृष्ठ छह पर

एपीडब्ल्यू ने असम के स्पीकर से संपर्क कर विस निधि के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की

गुवाहाटी। असम लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यू) ने असम विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा सचिवालय में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस सप्ताह प्रस्तुत किया गया ज्ञापन, 31 मई को एपीडब्ल्यू द्वारा जारी एक कड़े शब्दों वाले प्रेस विज्ञप्ति के बाद आया है, जिसमें संगठन ने आरोप लगाया था कि पिछले पांच वर्षों में विधानसभा सचिवालय की गरिमा और कार्यप्रणाली से गंभीर रूप से समझौता किया गया है और अगस्त 2024 में एपीडब्ल्यू द्वारा पहली बार उठाई गई चिंताओं को तत्कालीन अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी को अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद अनसुलझा छोड़ दिया -शेष पृष्ठ छह पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

तमिलनाडु में चुनावी झटके के बाद इंडिया ब्लॉक से डीएमके की दूरी

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। एमके स्टालिन की पार्टी ने इस फैसले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। डीएमके ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस की मौजूदगी के कारण वह इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर वह हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। दरअसल, तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के साथ हाथ मिला लिया। टीवीके ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद से ही डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में खटास साफ दिखाई देने लगी थी। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि डीएमके, कांग्रेस से दूरी बना सकती है।

शिलांग में एनईसी की 73वीं बैठक

अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास और विजन 2047 पर की चर्चा

शिलांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर, मुख्यमंत्री कॉनराड के. सांग्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और डोनर मंत्रालय के सचिव संजय जाजू शामिल हुए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक से पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई योजनाओं और परियोजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उत्तर पूर्वी परिषद ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सभी आठ राज्य *विकसित भारत 2047* के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विकास योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय और एनईसी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिषद ने वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दी है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों पर सीएम पेमा खांडू ने कहा कि यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और हम इस तरह के दावों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। हमारी सीमा चीन से नहीं, बल्कि तिब्बत से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ तिब्बत से लगती है, 1962 के या उस दौर के बुनियादी ढांचे की तुलना आज के समय से करना काफी गुमराह करने वाला है। पिछले 12 वर्षों में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को जबरदस्त बढ़ावा दिया है, उससे ये इलाके अब बहुत ज्यादा सुलभ हो गए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने कहा कि सभी आठ राज्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी आर्थिक संभावनाओं और विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया। साथ ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा भी साझा की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर देते हैं। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बैठक में व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें दो उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा

शिलांग। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का भी आकलन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, आज अमित शाह शिलांग से अगरतला पहुंचे। शुक्रवार को वह कई बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेंगे। वह अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध, तस्करी और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीमा से सटे आबादी वाले क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अमित शाह अगरतला पहुंच हैं। अगरतला में गृह मंत्री बीएसएफ, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बांग्लादेश सीमा के दौरे के दौरान गृह मंत्री कुछ आधारभूत परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।

योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मिलेगी नई पहचान : मोदी

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि योग मानवता के लिए भारत का शाश्वत उपहार है, जो मन, शरीर और आत्मा को एकाकार कर अधिक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण विश्व की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि अहमदाबाद की धरती से विश्व खेल जगत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने चैंपियनशिप में भाग लेने आए विभिन्न देशों के खिलाड़ियों का भारत में स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद एक यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है और इस ऐतिहासिक नगर में इस वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मोदी ने कहा कि कुछ दिनों बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसका मुख्य आयोजन इस वर्ष कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि लगभग एक दशक पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसे 190 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। भारत का उद्देश्य अपनी प्राचीन परंपरा को मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना था। मोदी ने कहा कि विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में योगासन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी अपना स्थान बनाएगा।

गृह मंत्रालय पर कथित टिप्पणी को लेकर ममता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला सिलीगुड़ी साइबर अपराध पुलिस थाना में एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। शिकायत अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने दर्ज कराई है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने दो जून को कोलकाता के रानी रासमणि रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान ऐसे बयान दिए, जिनमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर संकेतात्मक आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार, यह पूरा मामला बांग्लादेश के नागरिक उस्मान हादी की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि उस्मान हादी की हत्या पिछले वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश में हुई थी और बाद में उनके कथित हत्यारे जनवरी में मेघालय सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें राज्य की विशेष कार्य बल ने गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने आरोप लगाया कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं, तब वे इस मुद्दे को सीधे गृह मंत्रालय के समक्ष उठा सकती थीं।

भारत-वेनेजुएला के बीच ऊर्जा साझेदारी पर जोर, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा

नई दिल्ली (हि.स.)। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान दोनों देशों ने खनन क्षेत्र में संभावित सहयोग और संसाधनों के आकलन को लेकर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, जबकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण तेल का बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में हम दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बेहतरीन तालमेल देखते हैं। टंडन ने बताया कि भारत की स्पॉट खरीद में वेनेजुएला इस महीने तीसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में ऊर्जा साझेदारी प्रमुख विषय रही। वेनेजुएला का ऊर्जा क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और वह भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक स्थिर मांग वाले साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्तरों पर सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि वेनेजुएला केवल ऊर्जा संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोना, हीरे और अन्य खनिज संपदाओं से भी समृद्ध देश है। दोनों पक्षों के बीच खनन क्षेत्र में संभावित सहयोग और संसाधनों के आकलन को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर आगे कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला अब सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र के अलावा खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण निर्माण, ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में भी भारतीय कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं।

हाथी के हमले से मरे व्यक्ति के घर पहुंचे बीटीसी के उप-प्रमुख

कोकराझाड़ (हिंस)। कुमारीकाटा क्षेत्र के सोमलिगुरी गांव में जंगली हाथी के हमले में फाउलुस बसुमतारी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बोड़ोलैंड टेरीटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के उप-प्रमुख विजित गौरा नार्जारी गुरुवार को मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दुख में सहभागी बने। इस दौरान नार्जारी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

लोकसभा चुनाव 2029 से पहले परिसीमन की तैयारी

केंद्र सरकार विवादों से बचने के लिए क्षेत्रीय दलों से बना रही सहमति

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के चुनावी इतिहास में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने परिसीमन पर नए सिरे से जोर देने के लिए राजनीतिक सहमति बनाना शुरू कर दिया है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक नया विधेयक लाने और इस प्रक्रिया को पूरा करने की संभावना तलाश रही है। इस संवेदनशील और बड़े राजनैतिक बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत कर आम सहमति बनाने की कवायद तेज कर दी है। जिन दलों से परामर्श किया गया है उनमें डीएमके और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं, साथ ही अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ भी चर्चा जारी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दशकों में पहली बार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और उस बहस को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसने लंबे समय से भारत के राजनीतिक परिदृश्य को विभाजित किया हुआ है। लोकसभा सीटों का वर्तमान आवंटन 1971 की जनगणना के बाद स्थिर किए गए जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, लोकसभा में वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन संवैधानिक परिसीमन समाप्त होने के बाद किसी भी परिसीमन प्रक्रिया से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन में बदलाव आने की आशंका है। एनडीटीवी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र उन राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं से अवगत है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है और एक ऐसे फार्मूले की दिशा में काम कर रहा है जिसे व्यापक राजनीतिक स्वीकृति मिल सके। सरकार का मानना है कि परिसीमन को राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दा बनने से बचाने के लिए आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा, इसलिए चर्चाएं निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बनाए रखते हुए चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की क्षत्रीय दलों के साथ हुई अब तक की बातचीत सकारात्मक रही है। सरकार कानून को आगे बढ़ाने से पहले एक व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। एक बार परामर्श पूरा हो जाने और व्यापक सहमति बन जाने के बाद, केंद्र द्वारा विधेयक पर अगला कदम उठाने की उम्मीद है। यह परिसीमन आगामी लोगसभा चुनाव 2029 से पहले सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक अभ्यासों में से एक बनने की संभावना है, जिसका संसदीय प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और देश के भविष्य के चुनावी मानचित्र पर प्रभाव पड़ेगा।

सीबीएसई ने त्रि-भाषा फार्मूला मनमाने ढंग से लागू किया : कांग्रेस

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली और कक्षा 9 एवं 10 में त्रि-भाषा फार्मूले को जल्दबाजी में और मनमाने तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को कहा कि दिसंबर 2025 में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश को स्पष्ट रूप से मंजूरी दी थी कि एनसीईआरटी द्वारा ग्रेडेड पाठ्यपुस्तकें जारी होने तक मौजूदा भाषा व्यवस्था जारी रहे। इस निर्णय पर तत्कालीन चेयरमैन और सचिव ने हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बावजूद मई 2026 में सीबीएसई ने परिपत्र जारी कर 01 जुलाई से कक्षा 9 एवं 10 में तीसरी भाषा जोड़ने का निर्देश दिया और स्कूलों से कहा कि वे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से 9वीं के छात्रों को पढ़ाएं। उन्होंने सवाल किया कि पिछले छह महीनों में आखिर क्या बदला, जबकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 एवं 10 के लिए कोई नई भाषा पाठ्यपुस्तक जारी नहीं की है। इस कदम का कोई शैक्षणिक औचित्य नहीं है और इससे लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय और उसकी स्वायत्त संस्थाएं शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही हैं। रमेश ने कहा कि जब जवाबदेही की बात आती है तो सीबीएसई के अधिकारियों को पद से हटाया जाता है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

मुजफ्फरपुर में लगी आग, अस्पताल जाने की जगह दिल्ली रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार

पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज गुरुवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। हालांकि उनकी दिल्ली यात्रा ऐसे समय हुई जब मुजफ्फरपुर जिले में एक प्राइवेट अस्पताल में आज सुबह आग लग गई, हादसे में कम से कम 4 लोग मारे गए, लेकिन वह अस्पताल का दौरा करने की जगह दिल्ली चले आए। यही नहीं हादसे के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आरजेडी ने इस यात्रा पर निशाना साधा है।

मुजफ्फरपुर जिले में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू (गहन चिकित्सा कक्ष) में आज गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। कई बीमार लोग घायल हो गए। जिले के जिलाधिकारी ने घटना के बारे में कहा कि हमें तड़के अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली। इस आगजनी में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। जबकि आईसीयू में करीब 13 से 15 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वार्ड में आग तेजी से फैल गई, जिससे आईसीयू धुएं से भर गया और मरीजों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई हुई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि वह प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहा है तथा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ मरीजों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण अग्निकांड की घटना होने के बाद भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दोपहर 12 बजे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही अस्पताल का दौरा किया। बजाए इसके कि वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। निशांत कुमार की दिल्ली यात्रा पर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने निशाना साधते हुए एक्स पर कहा कि मुजफ्फरपुर में नियमों की अनदेखी कर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चल रहे अवैध अस्पताल में आग लग जाने से कई लोग मारे गए अनेक झुलस गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देखिए इस दुखद घटना पर बिना जवाबदेही के हाथ जोड़कर और मुस्करा कर गर्मी में दिल्ली घूमने निकल गए।

कर्नाटक में कांग्रेस से मुस्लिम समाज की मांग, हमारे वोट से जीते, 5 कैबीनेट मंत्री बनाओ

नई दिल्ली। कर्नाटक में मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उलेमाओं ने राज्य मंत्रिमंडल में समुदाय के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है और कांग्रेस सरकार से पांच मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में आई है और समुदाय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का हकदार है। बुधवार शाम हुबली के बेल्लीनगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की बैठक में यह मांग उठाई गई, जहां विशेष प्रार्थनाएं भी की गईं। बैठक के दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बीजेड जमीर अहमद खान, एनए हारिस, तनवीर सैत और सलीम अहमद को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठाई गई। नेताओं ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को पहले ही एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद दिया जा चुका है; इसलिए अब समुदाय के चार अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए, एक धार्मिक नेता ने चेतावनी दी कि कैबिनेट में पांच मुस्लिम नेताओं को शामिल न करने पर भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पांच मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक अन्य उलेमा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने लगातार कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ वोट दिया है कि वह कर्नाटक में सरकार बनाएगी।

कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, आधा दर्जन राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बदलेंगे!

नई दिल्ली। डीके शिवकुमार के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने बीके हरिप्रसाद को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अब कांग्रेस संगठन में देश भर में बड़े फेरबदल की उम्मीद है। अपनी राज्य सरकारों के कील-कांटे दुरुस्त करने के बाद अब कांग्रेस संगठन में बदलावों की तैयारी की जा रही है। आधा दर्जन राज्यों के प्रभारी और आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने वाले हैं, तो कई निष्क्रिय सचिवों की संगठन से छुट्टी हो सकती है। पिछले हफ्ते, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ बदलावों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग की थी। कांग्रेस मुख्य रूप से उन राज्यों पर ध्यान दे रही है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल के आखिर में चुनाव होने की उम्मीद है। पंजाब को छोड़कर, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। सूत्रों के मुताबिक, सबसे पहले प्रभारियों की बात करें तो तमिलनाडु, हरियाणा, असम, राजस्थान, बंगाल समेत आधा दर्जन राज्यों के प्रभारियों को बदला जाना है। हाल में कांग्रेस ने गिरीश चोडनकर को गोवा और बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं पंजाब अध्यक्ष राजा वड़िंग, यूपी अध्यक्ष अजय राय, महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव और बंगाल अध्यक्ष शुभंकर सरकार समेत कई प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। वहीं, राजस्थान में 5 साल से ज्यादा वक्त से अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सचिन पायलट को भेजे जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही तमिलनाडु और मणिपुर के अध्यक्षों का बदला जाना तय है। हाल में कर्नाटक में सीएम पद में परिवर्तन हुआ है। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गये हैं। वहीं, सिद्धारमैया को कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। उनके अलावा कार्यसमिति से कुछ उम्रदराज नेताओं की जगह नए लोगों को जगह देने पर भी विचार हो रहा है। संगठन में बदलावों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच चर्चा का सिलसिला शुरू हो चुका है।

यूएनएससी की पावर टेबल से पाकिस्तान बाहर, पांच नए देशों की एंट्री

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पाकिस्तान का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त होने वाला है, क्योंकि पांच नए देशों को विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनयिक संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 3 जून को हुए यूएनएससी चुनावों के एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में, किर्गिस्तान ने अपने इतिहास में पहली बार सुरक्षा परिषद में सीट हासिल की। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को भी दो साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नव निर्वाचित देश पाकिस्तान, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस और सोमालिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो रहा है। नए सदस्य आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2027 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर, 2028 तक अपने कार्यकाल को जारी रखेंगे। इस वर्ष के चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि किर्गिस्तान का सुरक्षा परिषद में ऐतिहासिक प्रवेश था। रिपोर्टों के अनुसार, पांच उपलब्ध सीटों के लिए सात देशों ने चुनाव लड़ा। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे ने पहले दौर के मतदान में जीत हासिल की। अंतिम सीट के लिए किर्गिस्तान और फिलीपींस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। तीन अतिरिक्त दौर के मतदान के बाद, किर्गिस्तान विजयी हुआ और सुरक्षा परिषद में अपनी पहली सदस्यता प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट जीतने के लिए, उम्मीदवार देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने होंगे।

भारत-बांग्लादेश सीमा मुद्दों पर दिल्ली में होगी अहम बैठक

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 57वां डीजी स्तर का बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कांफ्रेंस 8 से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) करेगा। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे, जबकि बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल

का नेतृत्व मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दकी करेंगे। चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और समन्वय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल सीमा पार अपराधों को रोकने, बांग्लादेशी अपराधियों की भारत में घुसपैठ रोकने, सीमा पर बाड़ तोड़ने की घटनाओं, सीमा बाड़ निर्माण, सीमा अवसंरचना विकास और आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके अलावा बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा किए जाने वाले हमलों की घटनाओं को रोकने तथा बांग्लादेश में सक्रिय भारतीय उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल हैं। बीएसएफ के अनुसार, दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछला बीएसएफ-बीजीबी डीजी स्तर का सम्मेलन 25 से 28 अगस्त 2025 के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच डीजी स्तर की यह सीमा समन्वय बैठक 1975 से आयोजित की जा रही है।

असम भाजपा विश्व पर्यावरण दिवस को एक विशाल पौधरोपण अभियान के साथ मनाएगी

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने न केवल असम के बहुआयामी विकास को गति दी है, बल्कि राज्य की पारिस्थितिक संपदा के संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी 5 जून को पूरे असम में विश्व पर्यावरण दिवस को एक व्यापक और विस्तृत तरीके से मनाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर, पार्टी ने पूरे राज्य में एक करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। भाजपा के अनुसार, पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान, कथित तौर पर निजी स्वार्थों और मुनाफे की होड़ में जंगलों को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया था। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों और आर्द्रभूमियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और प्राकृतिक आवासों का क्षरण एक दुखद रूप से आम बात बन गई थी। गैंडों के शिकार की घटनाएं अक्सर सुर्खियों में छाई रहती थीं, जबकि राज्य की अमूल्य प्राकृतिक विरासत लगातार उपेक्षा का शिकार होती रही। इसके विपरीत, सर्बानंद सोनोवाल और उसके बाद डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राजग सरकारों ने पर्यावरणीय क्षरण के इस लंबे दौर को समाप्त कर दिया। अतिक्रमण की गई वन भूमि और आर्द्रभूमियों के विशाल हिस्सों को वापस हासिल किया गया, वन्यजीव आवासों को बहाल किया गया, और असम के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक बयान में असम प्रदेश भाजपा ने पिछले एक दशक में राज्य के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और उसे मजबूत करने के लिए उठाए गए कई परिवर्तनकारी कदमों पर प्रकाश डाला। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने आज बताया कि अकेले पिछले पांच

वर्षों में ही अवैध अतिक्रमण से 25,000 एकड़ से अधिक वन भूमि को वापस हासिल किया गया है। पिछले वर्ष 9 और 10 नवंबर को ग्वालपारा के दाहिकाटा आरक्षित वन में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, लगभग 600 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाया गया और लगभग 1,150 बीघा वन भूमि को वापस उसके मूल स्वरूप में लाया गया। इसके बाद किए गए पौधरोपण और पारिस्थितिक बहाली के उपायों के परिणामस्वरूप, इन वापस हासिल किए गए आवासों में वन्यजीवों की धीरे-धीरे वापसी होने लगी है। दहिकाटा और बंदरमाथा आरक्षित वनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने से, लंबे समय से बाधित हाथियों के गलियारे फिर से खुल गए हैं। इससे मानव-हाथी संघर्ष में काफी कमी आई है और जंगली हाथी अपने प्राकृतिक क्षेत्र में आजादी से घूम-फिर पा रहे हैं। इसी तरह, गोलाघाट जिले के रेंगमा आरक्षित वन में, सरकार ने पहले ही लगभग 153 हेक्टेयर जमीन वापस हासिल कर ली है और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिया है। कार्बी आंगलोंग के धनसिरी और दलदली आरक्षित वनों में अतिक्रमण-मुक्त बहाली के प्रयासों ने भी बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों के लिए रास्ता खोल दिया है, जिनमें कई स्थानीय प्रजातियों को शामिल किया गया है। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के बड़े हिस्सों को वापस हासिल करने के बाद, वन्यजीवों की आवाजाही काफी आसान हो गई है, जिससे जानवरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊपरी असम का पोवाई जंगल, जो कभी अवैध कब्जे के कारण पारिस्थितिक पतन की कगार पर पहुंच गया था, उसने भी इसी तरह एक शानदार पुनरुद्धार देखा है। आज, इस पुनर्जीवित परिदृश्य में हाथियों, बाघों, भालुओं और जंगली घोड़ों की मुक्त आवाजाही सफल संरक्षण प्रयासों का एक प्रमाण है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई है। काजीरंगा, जो कभी अक्सर गैंडों के शिकार और वन्यजीव अपराधों की परेशान करने वाली खबरों से जुड़ा रहता था, आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। आगंतुकों की संख्या में लगभग 155,000 से बढ़कर 548,000 तक की भारी वृद्धि हुई है, जो डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत एक परिवर्तनकारी उपलब्धि को दर्शाती है। इसी तरह, मानस राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से भी उत्साहजनक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों ने मिलकर इन संरक्षित क्षेत्रों में 100,000 से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है। इसके परिणामस्वरूप, असम के इको-टूरिज्म क्षेत्र को अभूतपूर्व गति और जीवनशक्ति मिली है। पर्यटन को मजबूत करने के अलावा, इस बदलाव ने स्थानीय युवाओं, गाइडों, ड्राइवरों, होमस्टे संचालकों और छोटे उद्यमियों के लिए आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के नए रास्ते खोले हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों में आत्मविश्वास, अवसर और स्थायी समृद्धि को बढ़ावा मिला है। मेधी ने घोषणा की कि भाजपा 5 जून को पूरे असम में विश्व पर्यावरण दिवस को एक व्यापक और विस्तृत तरीके से मनाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर, पार्टी ने पूरे राज्य में 10 मिलियन (1 करोड़) पौधे लगाने का संकल्प लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर, पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ में कम से कम पांच फलदार पेड़ लगाएंगे, जबकि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी मां की प्यारी याद और सम्मान में एक पौधा समर्पित करेगा, जिससे यह अभियान एक पर्यावरणीय मिशन और मातृत्व के प्रति एक हार्दिक श्रद्धांजलि, दोनों बन जाएगा।

म्यांमार संकट के कारण मिजोरम पर दबाव और शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है : सीएम

शिलांग। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को म्यांमार में संघर्ष से भाग रहे लोगों के बढ़ते प्रवाह पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विस्थापित व्यक्तियों के निरंतर आगमन से राज्य के संसाधनों और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की वार्षिक आम बैठक के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अस्थिरता में कमी आने के कोई खास संकेत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार में मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, अधिक लोग शरण मांग रहे हैं। संभावना है कि विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, और यह राज्य के लिए एक बोझ बन गया है। म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला मिजोरम, पड़ोसी देशों में हिंसा और राजनीतिक अशांति से भाग रहे लोगों के लिए एक प्रमुख शरणस्थल के रूप में उभरा है। राज्य की भौगोलिक स्थिति ने इसे क्षेत्रीय मानवीय संकटों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया है। गृह मंत्री के. सपडांगा द्वारा हाल ही में मिजोरम विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, म्यांमार से आए लगभग 29,000 शरणार्थियों को वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में ठहराया जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि मिजोरम में विस्थापित लोगों की कुल संख्या 38,000 से अधिक है, जिसमें म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों के साथ-साथ पड़ोसी मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोग भी शामिल हैं। हालांकि, मानवीय संगठनों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। अनुमानों के अनुसार, राज्य में 50,000 से 60,000 विस्थापित व्यक्ति रह रहे होंगे, जिनमें से कई आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त शिविरों के बाहर रह रहे हैं और पंजीकृत नहीं हैं। म्यांमार की सेना द्वारा फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के तुरंत बाद शरणार्थियों का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे पूरे देश में व्यापक अशांति और सशस्त्र प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। तब से लेकर अब तक हजारों नागरिक, विशेष रूप से चिन समुदाय के सदस्य, बढ़ती हिंसा से सुरक्षा की तलाश में मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं। मिजोरम में स्थानीय समुदायों ने चिन शरणार्थियों के आगमन का काफी समर्थन किया है। चिन और मिजो लोगों के बीच साझा जातीय जड़ों, सांस्कृतिक समानताओं और लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संबंधों ने चर्चों, नागरिक समाज समूहों और स्थानीय निवासियों के नेतृत्व में मानवीय प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को शरणार्थियों को स्वीकार करने से हतोत्साहित करने के रुख के बावजूद, मिजोरम ने संघर्ष से भाग रहे लोगों को आश्रय और सहायता प्रदान करना जारी रखा है। राज्य के अधिकारियों ने सामुदायिक संगठनों और धार्मिक संस्थानों के सहयोग से राहत प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

मणिपुर हाईकोर्ट ने छह नागा नागरिकों के अपहरण पर की गई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

इंफाल। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह से अधिक समय पहले लेइलोन वाइफेई गांव से कथित तौर पर अपहरण किए गए छह नागा नागरिकों के लापता होने के संबंध में सोमवार तक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश घटना को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया, जो कथित तौर पर 13 मई को हुई थी। लापता हुए छह लोग तब से लापता हैं, जिससे समुदाय के

सदस्यों और नागरिक समाज समूहों में चिंता बढ़ गई है। यह जनहित याचिका नागा वकीलों के संघ के अध्यक्ष टी. मार्क खपाई द्वारा दायर की गई थी और इसे अधिवक्ता डी. जूलियस रियामेई द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याचिका में लापता व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयासों में तेजी लाने और जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिका में राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को लापता व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया है। हालांकि, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि एजेंसी को अभी तक इस मामले के संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई, जांच की वर्तमान स्थिति और लापता व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयासों में हुई प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले की आगे की सुनवाई 8 जून को होनी है, जब राज्य सरकार द्वारा अदालत के समक्ष अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है।

मीन निगम घोटाले के मुख्य आरोपी पद्मकांत हजारिका फिर अदालत में पेश

गुवाहाटी (हिंस)। असम मत्स्य विकास निगम (एएफडीसी) के बहुचर्चित करोड़ों रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी पद्मकांत हजारिका को गुरुवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच लगातार जारी है और जांच एजेंसियां कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। इसी बीच, पुलिस ने गुवाहाटी के हाथीगांव क्षेत्र स्थित शेवाली पथ में गुरुवार को एक आवास पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एएफडीसी में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान पुलिस पद्मकांत हजारिका को भी अपने साथ लेकर गई। जांच दल ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की तलाश में घर की गहन जांच की। बताया गया है कि जिस घर में छापेमारी की गई, उसमें पद्मकांत हजारिका का एक रिश्तेदार रहता है। पुलिस अधिकारियों ने कई दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच की है, जिन्हें मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एएफडीसी घोटाले की जांच के सिलसिले में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) पद्मकांत हजारिका को गत 31 मई को उड़ीसा के पुरी से गिरफ्तार किया गया था। उन पर निगम में भर्ती प्रक्रिया और जलाशयों (बील) के पट्टों के आवंटन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि विभाग में कुछ नियुक्तियां कथित रूप से धन लेकर की गईं तथा भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता की अनदेखी की गई।

कोकराझाड़ : एमसीएलए और कार्यकारी सदस्यों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती

कोकराझाड़ (हिंस)। बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) सरकार ने खर्चों में कटौती के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एमसीएलए और कार्यकारी सदस्यों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने का फैसला किया है। यह निर्णय कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया। परिषद ने आगामी छह माह तक इस कटौती को लागू रखने का निर्देश जारी किया है। बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी ने बीती रात बैठक के बाद बताया कि मध्य-पूर्व में युद्ध जैसे हालात और उससे उत्पन्न वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने तथा सरकारी खर्चों में कमी लाने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है। परिषद का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है।

सतिया में असमिया पुस्तक *गोधूलार बिपरित चिंता* पुस्तक का विमोचन

विश्वनाथ (विभास)। दोलोंगगुड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक तथा प्रतिभाशाली युवा लेखक मृदुल बरुवा द्वारा संकलित असमिया पुस्तक *गोधूलार बिपरित चिंता* नामक पुस्तक का विमोचन सोमवार को सतिया प्रेस क्लब के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में बिश्वनाथ चारियाली के पत्रकार बसंत बोरा द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता बिश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. भक्त प्रसाद गौतम ने की। प्रख्यात महिला लेखिका मयुरखी महंत सैकिया ने विशेष वक्ता के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। बैठक में निरंजन सैकिया, अनुश्री अधिकारी, प्रत्यूष भुइयां, मृणाल गोस्वामी सहित बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कछार में 4.5 करोड़ की मादक पदार्थ बरामद, तीन महिला समेत छह गिरफ्तार

कछार (हिंस)। असम के विभिन्न जिलों में नशा-विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने कछार जिले की विभिन्न इलाकों में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में तीन महिला समेत छह ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं, लगभग 4.5 करोड़ मूल्य की मादक पदार्थ भी बरामद किया है। कछार जिला पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को बताया कि उदारबंद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, इंट्रा बी-10 ट्रक (एएस-11डीसी-8629) से कुल 8010 बोतलें (100 एमएल) कोडीन कफ सिरप और 150 पैकेट ट्रामाडोल टैबलेट (प्रत्येक पैकेट में 10 स्ट्रिप और एक स्ट्रिप में 24 टैबलेट, यानी कुल 36,000 टैबलेट) बरामद की गईं।

जनसमस्याओं के समाधान को लेकर विधायक और बीटीसी कार्यकारी सदस्य ने की बैठक, विकास का दिया आश्वासन

कोकराझाड़ (विभास)। बोड़ोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीसीटी) के विकास और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में बीटीसी के कार्यकारी सदस्य (ईएम) करमेश्वर राय और बउखूंगारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपम चंद्र राय ने कोकराझाड़ जिले के शक्तिआश्रम स्थित खुकषी गांव का दौरा किया। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस विशेष जन-संवाद सभा में विधायक रूपम चंद्र राय और ईएम करमेश्वर राय ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान क्षेत्र के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं, विकास कार्यों और अन्य व्यक्तिगत व सामूहिक चुनौतियों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद बीटीसी के कार्यकारी सदस्य करमेश्वर राय और विधायक रूपम चंद्र राय ने संयुक्त रूप से सभी समस्याओं के जल्द निराकरण का पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है और जनहित की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। बैठक में उपस्थित स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के सीधे हस्तक्षेप पर संतोष जताया और क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

No.DPRD/BTC/15th FC/Bak-10/2025-26/ *Dated Kokrajhar the 4th June, 2026*

NOTICER INVITING TENDER

Sealed tenders with a validity period of 90 (ninety) days from the date of receipt in prescribed from affixing non-refundable court fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees eight and paisa twenty five) only subsequently to be drawn up in printed F-2 form are hereby invited from the Govt. registered PWD (Roads/ Building), P&RD, Irrigation/ Water Resources / PHE others Govt. Contractor's under Class-I (A, B, C), Class-II and Class-III category from approved firm according to tender limit of eligibility for the following works under the award of 15th FC (RLBs) Untied Basic Grant for the Financial year 2024-25 (1st & 2nd Inst.) during 2025-26 and will be received in the office of the undersigned up to 2.00 pm on **26/06/2026** and will be opened on the same date and place at 2.15 pm in the presence of willing contractors or their authorized agents.

Sl. No.	Name of Dev. Block	Name of Scheme	A/A amount (Rs. In Lakh)	Tender Amount (Rs.)	Earnest Money (ST, SC, OBC- 1% & Gen-2%)	Cost of Tender in Rs.
1	Tihu-Barama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Barama VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
2	Tihu-Barama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Debachara VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
3	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Bangnabari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
4	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Barabri VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
5	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Bathoupuri VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
6	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Bhogpara VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
7	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Chaibari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
8	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Adalbari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
9	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Amabari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
10	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Athiabari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
11	Baska	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Chanbarikhuti VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
12	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at No.1 Dakhin Howly VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
13	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at No. 2 Pub Howly VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
14	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at No. 3 Paschim Howly VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
15	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at No. 4 Uttar Howly VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
16	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at No. 5 Mairajhar Pather VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
17	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Barphena VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
18	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Godhuligaon VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
19	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Golagaon VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
20	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Jalagaon VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
21	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Rabanguri VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
22	Jalah	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Jalah VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
23	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Bahbaru VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
24	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Banmaja VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
25	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Chunbari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
26	Gobardhana	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Dhekiajani VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
27	Dhamdhama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Angardhowa VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
28	Dhamdhama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Baganpara VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
29	Dhamdhama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Bagulamari VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-
30	Dhamdhama	Installation of 9 mtr. Solar High Mast light at Ghoramarai VCDC	8.50	Rs.8,41,668/-	ST,SC,OBC- 1% & Gen-2%	Rs. 252/-

Time of Completion :- 3 Months

Pre-Bid meeting date & time :- 19/06/2026

Details NIT may be seen in all working days in the office of the undersigned. Tender paper will be issued to the Contractors or their authorized agent up to 12.00 Noon on all working days from **4/06/2026** to **26/06/26** in the office of the undersigned on payment of in the form of Banker cheque/ Demand draft of any nationalized Bank (Preferable SBI) duly pledged to the **Director, P&RD, BTC, Kokrajhar**. The Cost of tender (Non-Refundable) must be in the form of Demand Draft/ Banker Cheque of a Nationalized Bank drawn in favour of the **Principal Secretary, BTC, Kokrajhar** and payable at SBI, Kokrajhar to be deposited 0.03%.

Sd/- Director,
Panchayat & Rural Development,
BTC, Kokrajhar

IPR(BTC)/C/2026-27/429

संपादकीय

यह शिमला की आफत है

शिमला तेरे बाजुओं में कितना सुकून बचा, हम चल के बताएं या तेरे जख्म देखें। वकील सड़क पर हो, तो अदालत न्याय कैसे देगी और कानून व्यवस्था सड़क पर हो, तो शिकायत किससे करें। सोमवार के दिन हाई कोर्ट परिसर सड़क पर बिफर गया, तो आवाजाही का तकाजा कांटों से भर गया। प्रदेश को अंदाजा ही नहीं कि हाई कोर्ट में कितने वकील हर दिन अपनी हाजिरी का सुकून सड़क पर हारते हैं या मारामारी के आलम में पार्किंग में अपने वाहन की वजह ढूंढते हैं। पार्किंग की गुंजाइश में यह बावेला सरकार बनाम वकील नहीं होना चाहिए था, लेकिन शिल्ली चौक-छोटा शिमला की प्रतिबंधित सड़क पर आकर सारा माहौल कुर्बान हो गया। दोनों पक्ष अपनी कर्त्तव्यपरायणता के परिचय में ड्यूटी का अमृत्व पीना चाहते हैं, लेकिन असंतुलित राजधानी का कवच टूट गया। पुलिस को प्रतिबंधित जमीन पर पार्क हुए वाहन हटाने थे, लेकिन इस बार वकील समुदाय ने विकल्प पूछ लिया या यह बता दिया कि यह आम नागरिक का भी हक है कि शिमला की बाहों में अपना अधिकार-अपनी सुविधा पूछे। जाहिर है एक ही शहर में दो मानदंड नहीं हो सकते। एक से परमिट पूछा जाए और दूसरा सरे राह गुजर जाए। यह शिमला की आफत है कि यहां वीआईपी होना एक शौक है या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जमात हर क्षण आम नागरिक को छोटा दिखाती है। वकीलों की जरूरत और जिद में फर्क ढूंढा जा सकता है। जरूरत यह कि हाई कोर्ट परिसर में पैरवी के सबूत जब कारगर होंगे, तो वकील मशगूल होंगे। अब शिमला का आचरण बदला और बदल गई है दिनचर्या की गति। अब अगर वीआईपी फुर्सत में हो, तो वाहनों की आजमाइश में माल रोड भी सिसक उठेगा। आखिरकार शिमला के वकील हैं तो शहर के ही पैरोकार। ये सफल हैं तो गाड़ियां भर-भर के अदालतों के बाहर तक आएंगी। सरकार को केवल यह करना है कि वकीलों के वाहनों को चैन से ठहरने की जगह दे दी जाए। इसके लिए प्रतिबंधित मार्गों के विकल्प चाहिएं और यह दिक्कत जिला स्तर के अदालती परिसरों में भी है। विडंबना यह भी है कि अदालतों को खुदा मानने वाले फरियादियों के पक्ष में कोई नहीं सोचता। हर अदालत परिसर में वकील और जज साहेबान महानुभाव हैं, लेकिन जो कानून की शरण में आते हैं, उनकी सुविधाओं की वकालत कभी नहीं होती। अगर हाई कोर्ट की अपीलों, सुनवाई चक्रों और कानूनी राहत की उम्मीदों से आए फरियादियों की गाड़ियों को भी पनाह देनी हो, तो सारा माहौल ही अव्यवस्थित हो जाएगा। अदालत परिसरों को भीड़ या शहरों के भीतर रखने के बजाय बाहर ले जाना होगा। पिछले चालीस सालों से हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग धर्मशाला के लिए हो रही है। अगर यह मांग पूरी हो जाए, तो बहुत सारे मामले और पैरवी करते वकील भी छंट जाएंगे। इतना ही नहीं शिमला को अपने पुराने नूर में बरकरार रखने के लिए समीपवर्ती वाकनाघाट में एक प्रशासनिक-कर्मचारी शहर के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि बड़े कार्यालय, अदालतें तथा सरकारी आवास वहां स्थानांतरित किए जा सकें। यहां मसला वकील बनाम सरकार नहीं है, बल्कि शहरी विकास की जरूरतों व सुविधाओं का है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों को 'स्टेट कैपिटल रीजन' के तहत विकसित करने की जरूरत है। समूचे हिमाचल को भी 'कलस्टर सिटी प्लानिंग' के तहत विकसित करें ताकि दो या तीन शहर मिलकर सुविधाओं का विकास उपलब्ध जमीन को देख कर करें। हर शहर के लिए ट्रैफिक प्लान बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि बढ़ते वाहनों का बोझ सड़कों को ही संकरा न कर दे।

हाई कोर्ट परिसर सड़क पर बिफर गया, तो आवाजाही का तकाजा कांटों से भर गया। प्रदेश को अंदाजा ही नहीं कि हाई कोर्ट में कितने वकील हर दिन अपनी हाजिरी का सुकून सड़क पर हारते हैं या मारामारी के आलम में पार्किंग में अपने वाहन की वजह ढूंढते हैं। पार्किंग की गुंजाइश में यह बावेला सरकार बनाम वकील नहीं होना चाहिए था, लेकिन शिल्ली चौक-छोटा शिमला की प्रतिबंधित सड़क पर आकर सारा माहौल कुर्बान हो गया। दोनों पक्ष अपनी कर्त्तव्यपरायणता के परिचय में ड्यूटी का अमृत्व पीना चाहते हैं, लेकिन असंतुलित राजधानी का कवच टूट गया। पुलिस को प्रतिबंधित जमीन पर पार्क हुए वाहन हटाने थे, लेकिन इस बार वकील समुदाय ने विकल्प पूछ लिया या यह बता दिया कि यह आम नागरिक का भी हक है कि शिमला की बाहों में अपना अधिकार-अपनी सुविधा पूछे। जाहिर है एक ही शहर में दो मानदंड नहीं हो सकते। एक से परमिट पूछा जाए और दूसरा सरे राह गुजर जाए। यह शिमला की आफत है कि यहां वीआईपी होना एक शौक है या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जमात हर क्षण आम नागरिक को छोटा दिखाती है। वकीलों की जरूरत और जिद में फर्क ढूंढा जा सकता है। जरूरत यह कि हाई कोर्ट परिसर में पैरवी के सबूत जब कारगर होंगे, तो वकील मशगूल होंगे। अब शिमला का आचरण बदला और बदल गई है दिनचर्या की गति। अब अगर वीआईपी फुर्सत में हो, तो वाहनों की आजमाइश में माल रोड भी सिसक उठेगा।

नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

ललित गर्ग

वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" (टमंज प्चेजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है।

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" (टमंज प्चेजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण-ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है। (राजनीतिक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म) पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और

भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।' आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है। आवश्यकता इस चेतना को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदलने की है। समाधान क्या है? सबसे पहले विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, पूरक मानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बनाना, वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप देना और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं से यह कार्य संभव नहीं होगा, इसके लिए समाज, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिकों की साझी भागीदारी चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को राजनीतिक एजेंडा बनाना होगा। जिस प्रकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दे बनते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हरित विकास और जलवायु सुरक्षा भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनें। मतदाता अपने प्रतिनिधियों से पर्यावरण संबंधी दृष्टि और प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न पूछें। जब जनता पर्यावरण को प्राथमिकता देगी, तब राजनीति भी उसकी ओर मुड़ेगी। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय चेतना को व्यवहारिक रूप से शामिल करना होगा। बच्चों और युवाओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के व्यावहारिक संस्कार दिए जाने चाहिए। चौथा, हमें अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाना होगा। अत्यधिक उपभोग, अपव्यय और सुविधावादी संस्कृति ने पर्यावरणीय संकट को बढ़ाया है। संयमित उपभोग, पुनर्चक्रण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और प्रकृति के प्रति संवेदनशील जीवनशैली ही स्थायी समाधान दे सकती है। यह दृष्टि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों में पहले से विद्यमान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमें यह स्मरण कराता है कि पर्यावरण का प्रश्न केवल पेड़-पौधों या नदियों का प्रश्न नहीं है यह मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हमने समय रहते अपनी नीतियों, विकास मॉडल और जीवनशैली में परिवर्तन नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। लेकिन यदि हम सजगता, वैज्ञानिक दृष्टि, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहभागिता के साथ आगे बढ़ें, तो संकट को अवसर में बदला जा सकता है। भारत के पास विश्व को नई दिशा देने की क्षमता है। प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, अहिंसा, संयम और संतुलित विकास की भारतीय दृष्टि आज पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि पर्यावरण को विकास का विकल्प नहीं, विकास का आधार माना जाए। यही विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश है, यही भविष्य की सुरक्षा का मार्ग है और यही पृथ्वी के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी भी।

देश | दुनीया से

प्रकृति के बदलते मिजाज को लेकर गंभीरता जरूरी

महात्मा गांधी ने वर्ष 1928 में ही उत्पादन और खपत के पश्चिमी मॉडल के चलते वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन की चेतावनी देते हुए कहा था— 'ईश्वर कभी नहीं चाहता कि भारत कभी पश्चिम की तरह औद्योगिकीकरण अपनाए।' साथ ही कहा था कि 'एक छोटे से द्वीप साम्राज्य (इंग्लैंड) के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को जंजीरों से जकड़ रखा है। यदि तीस करोड़ की आबादी वाले देश ने ऐसा आर्थिक शोषण किया तो पूरी दुनिया टिड्डियों की तरह बेकार हो जाएगी।' गांधीजी का मानना था कि देश को आज़ादी के बाद गरीबी दूर करने और लोगों के सम्मानजनक जीवनयापन की दृष्टि से आर्थिक विकास करना ही होगा। ऐसे में भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कहीं अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा। दुखद है कि आज़ाद भारत की सरकारों ने गांधी के विचारों को पूरी तरह बिसरा दिया। परिणामस्वरूप, जहां मानव जीवन प्रभावित हुआ, वहीं संसाधनों पर कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे से ग्रामीण और आदिवासी समाज बेदखली का शिकार हुआ। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के कारण प्रदूषण की समस्या ने भयावह रूप ले लिया। इस तबाही के विरोध में देश में चिपको, नर्मदा और मछुआरों के आंदोलन सामने आए। इसके उपरांत देश में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई और पारिस्थितिक नुकसान रोकने के लिए अनेक कानून बने। लेकिन सत्ता पर काबिज विभिन्न सरकारों ने समाज के व्यापक हित के बजाय निजी कॉर्पोरेट घरानों के हितों को सर्वोपरि मानकर उनके आगे झुकना उचित समझा। कॉर्पोरेट घरानों के निजी स्वार्थ के चलते प्रदूषित शहर, भयावह स्तर तक प्रदूषित वातावरण, मरती जीवनदायी नदियां, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, गिरता भूजल स्तर, खत्म होते जलस्रोत व जंगल, प्रदूषित मिट्टी, बंजर होती जमीन आदि पर्यावरण विनाश और तबाही के स्पष्ट सबूत हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बावजूद यह सिलसिला बेरोकटोक जारी है। वैश्विक स्तर पर देखें तो बीस वर्ष पहले हम सालाना आठ अरब मीट्रिक टन कार्बन वायुमंडल में छोड़ रहे थे, जिसका आंकड़ा बढ़कर आज डेढ़ गुणा से भी अधिक हो गया। इसके कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा जोरों पर है। प्रकृति का मिजाज बदल रहा है, और इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि दुनिया में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए

कोयला, तेल और गैस का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। भारत के संदर्भ में ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन रोकने के भारत के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने का ऐलान किया था, लेकिन पेरिस समझौते के मुताबिक डेढ़ डिग्री के लक्ष्य के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। देश को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने उत्सर्जन लक्ष्य नए सिरे से तय करने की आवश्यकता है, अन्यथा 2095 तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यदि कार्बन उत्सर्जन में कमी न आई तो जल संकट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ तेज गति से पिघलेगी, समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। नतीजन, दुनिया के कई देश पानी में डूब सकते हैं। समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर-महानगर जलमग्न होंगे, और लगभग 20 लाख से अधिक प्रजातियां सदा-सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। वहीं, सदियों से जीवन के आधार रहे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। विशेष रूप से बी-1, बी-2, बी-5 और बी-8 जैसी विटामिनों में कमी आएगी। बीमारियों से बचाने वाले जैव रसायनों में भी कमी आने की संभावना है। यदि पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ गया तो धरती का एक-चौथाई हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। वहीं 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे का शिकार होगा। नतीजतन, दुनियाभर में लगभग 150 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण यूरोप, मध्य अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा। चौंकाने वाली बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहले बीते चार दशकों में कम हो चुकी उर्वरा शक्ति वाली जमीन की सेहत बिगड़ने की दर अब सौ गुणा बढ़ गई है। उस हालत में भविष्य में दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। आने वाले 24 वर्षों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका को इस चुनौती का भीषण सामना करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में सदी के अंत तक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इसका असर खाद्यान्न, पेयजल और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। नतीजन आम आदमी का जीवन मुहाल हो जाएगा। प्रकृति के सारे उतार-चढ़ाव मानवता को संभलने के लिए चेतावनी हैं। पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम लोग इन्हें समझने और गंभीरता से लेने के बजाय नजरअंदाज कर रहे हैं। जरूरत इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करने की है मसलन, जीवनशैली में बदलाव व प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। ताकि पूरी पृथ्वी और मानवता के साथ-साथ इस ग्रह पर रहने वाले तमाम जीव-जंतुओं को विनाश से बचाया जा सके।

आप का | नजरीया

अब असली-नकली तृणमूल

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो गई है, लिहाजा पार्टी में टूट के पुख्ता आसार हैं। ममता ने मंगलवार को जहां 'प्रतीकात्मक धरना' दिया था, वहां तृणमूल के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से सिर्फ 7 ही पहुंचे। शेष 73 विधायक कहां थे? धरने से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें भी 20 विधायक ही पहुंचे। शेष 60 विधायक तब भी गायब थे, नतीजतन बैठक रद्द करनी पड़ी। धरने के वक्त समर्थकों की जो संख्या दिख रही थी, उससे ममता और तृणमूल के प्रति मोहभंग और अस्वीकार्यता स्पष्ट होती है। संसद के दोनों सदनों में तृणमूल कांग्रेस के 42 सांसद हैं, 80 विधायक हालिया चुनाव में जीत कर आए हैं और करारी पराजय के बावजूद 40 फीसदी से अधिक वोट तृणमूल को मिले हैं। इसके मद्देनजर पार्टी के अस्तित्व और समग्र स्वीकृति सरीखे सवाल नहीं उठाए जा सकते। सवाल यह मौजू है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की नियति भी शिवसेना और एनसीपी जैसी हो सकती है? आज 'असली शिवसेना' महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। जिस एनसीपी को शरद पवार ने गठित किया था, सालों तक सींचा भी था, आज वह पार्टी उन्हीं की घरेलू बहू सुनेत्रा पवार (दिवंगत अजित पवार की पत्नी) के कब्जे में है। अजित शरद पवार के सगे भतीजे थे और वह ही अजित की राजनीति के 'चाणक्य' थे। अजित ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और 'महायुति' की सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की प्रमुख भी हैं। हालांकि दोनों मामले शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। ममता बनर्जी ने दो बागी विधायकों-ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा-को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उसके बाद पार्टी के भीतर विद्रोह और असंतोष गहरा गए हैं। चुनाव तक तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रिजु दत्ता यहां तक दावा कर रहे हैं कि 80 में से 50 से अधिक विधायक टूटने नहीं, बल्कि पार्टी पर आधिपत्य और असलीपन का दावा ठोंकने पर आमादा हैं। ऐसे नेताओं की शिकायत है कि अब पार्टी में कोई भी नेतृत्व नहीं रहा। आई-पैक कंपनी पार्टी को धकिया रही है। ये नाराज विधायक स्पीकर (विधानसभा अध्यक्ष) से मिल कर साबित कर सकते हैं कि 65-70 फीसदी विधायक एकजुट हैं और ममता से अलग हैं, लिहाजा वे ही 'असली तृणमूल' हैं। उन्हें ऐसी मान्यता दी जाए। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि तृणमूल के 28 लोकसभा सांसदों में से अधिकतर पाला बदलने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। हालांकि असंतुष्ट सांसदों को संकेत दिए गए हैं कि वे दो-तिहाई सांसदों का एक नया गुट तैयार करें, एक प्रस्ताव पर अधिकृत हस्ताक्षर कराएं और लोकसभा स्पीकर को दें। स्पीकर ही अंतिम निर्णय लेंगे। भाजपा उस गुट को समर्थन दे सकती है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार भाजपा को अभी दलबदल के लिए 'लालायित' नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ऐतिहासिक और प्रचंड जनादेश मिला है। बहरहाल बंगाल में तृणमूल के विधायकों में 'नेता प्रतिपक्ष' को लेकर घमासान मचा है, लिहाजा कुछ विधायकों ने स्पीकर से शिकायत की है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जिस शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम भेजा गया होगा, उस प्रस्ताव पर उनके 'फर्जी हस्ताक्षर' किए गए हैं। सीआईडी इसकी जांच कर रही है और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी 8 जून की पेशी का नोटिस भेजा गया है। बहरहाल गंभीर सवाल यह है कि क्या एक चुनाव हारने पर ही पार्टी में इस कदर बगावत हो सकती है कि दोफाड़ की नौबत आ जाए? वैसे ममता बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस छीनना इतना आसान नहीं है।

ममता ने मंगलवार को जहां 'प्रतीकात्मक धरना' दिया था, वहां तृणमूल के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से सिर्फ 7 ही पहुंचे। शेष 73 विधायक कहां थे? धरने से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें भी 20 विधायक ही पहुंचे। शेष 60 विधायक तब भी गायब थे, नतीजतन बैठक रद्द करनी पड़ी। धरने के वक्त समर्थकों की जो संख्या दिख रही थी, उससे ममता और तृणमूल के प्रति मोहभंग और अस्वीकार्यता स्पष्ट होती है। संसद के दोनों सदनों में तृणमूल कांग्रेस के 42 सांसद हैं, 80 विधायक हालिया चुनाव में जीत कर आए हैं और करारी पराजय के बावजूद 40 फीसदी से अधिक वोट तृणमूल को मिले हैं। इसके मद्देनजर पार्टी के अस्तित्व और समग्र स्वीकृति सरीखे सवाल नहीं उठाए जा सकते। सवाल यह मौजू है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की नियति भी शिवसेना और एनसीपी जैसी हो सकती है? आज 'असली शिवसेना' महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। जिस एनसीपी को शरद पवार ने गठित किया था, सालों तक सींचा भी था, आज वह पार्टी उन्हीं की घरेलू बहू सुनेत्रा पवार (दिवंगत अजित पवार की पत्नी) के कब्जे में है। अजित शरद पवार के सगे भतीजे थे और वह ही अजित की राजनीति के 'चाणक्य' थे। अजित ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और 'महायुति' की सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की प्रमुख भी हैं। हालांकि दोनों मामले शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। ममता बनर्जी ने दो बागी विधायकों-ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा-को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

कुछ | अलग

तासीर बदलने की उम्मीद

बदलाव लाओ। हमारी हालत बदलो। हमें ऐसी शिक्षा दो जो इस बदलते हुए कम्प्यूटर, यन्त्रीकरण और डिजिटल जमाने में किसी काम भी आए। यह न हो कि इस बदलते युग में नए निपुण कामगार तो हमें मिलें नहीं। इनकी आसामियां, नौकरियां खाली रहें। उनके लिए हार कर रोबोट युग लाने की कल्पना की जाए। आदमी के हाथ की जगह स्वचालित मशीनें लें। आदमी की मौलिक अन्वेषक बुद्धि की जगह बनावटी बुद्धि और चेतना ले, लेकिन अगर सब कुछ इस्पाती बना, उसे यन्त्रीकरण कर दोगे, तो आपकी संवेदना किस कतार में दम तोड़ती नजर आएगी। उपेक्षित कतार? क्या लगातार बढ़ती हुई उस राहत और रियायत संस्कृति में जहां हाथ हिलाये बिना पेट भर जाए, अच्छा ओढ़ने-बिछौने की भावना पलती रहे, और आदमी तप-तपस्या, साधना और अध्यवसाय की जगह शार्ट कट की पतली गलियां तलाशने लगे? नजर आता है, एक दौड़ लगती है देश के कर्णधारों में नवनिर्माण की नहीं, उसके नाम पर तो अधूरी सडकें मिलती हैं, और बीच में छोड़ दिए गए अधबने पुल। आज उसकी जगह सपनों के ताजमहल नहीं, ताश महल खड़े किए जा रहे हैं, जो कब खड़े हुए, और किस फूंक से गिर गए, कुछ पता ही नहीं चला। कभी कहा जाता था, 'फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा।' अब न तो चिराग जलते हैं, और न उनकी रौशनी सुरक्षित रखने के लिए नया खून कटिबद्ध होते नजर आता है, बल्कि यहां तो फूंक अब एक दूसरे के कानों में मारी जाती है। उसकी कटुता फुसफुसाती नहीं, सारे माहौल में फैल जाती है। जहर फैलता है तो उसे काटने के लिए किसी अमृत की तलाश नहीं होती, बल्कि उसे काटने के लिए अधिक जहर फैलाया जाता है।

दृष्टि | कोण

हरियाली बचेगी, तो खुशहाली भी बचेगी

प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन का अवसर नहीं है, बल्कि पृथ्वी और मानव जीवन के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण भी कराता है। पर्यावरण संरक्षण किसी एक देश, सरकार या संस्था का विषय नहीं रह गया है। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय संकट के आंकड़े चिंताजनक हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया, जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो सूखा, बाढ़, हीटवेव और अन्य प्राकृतिक आपदाएं और अधिक विनाशकारी रूप ले सकती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वर्तमान में दुनिया में हर वर्ष लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जबकि इसका केवल लगभग 9 प्रतिशत ही पुनर्चक्रित हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल 80 लाख से 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंच जाता है। 1950 के दशक से अब तक 8.3 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, जिसका अधिकांश हिस्सा आज भी कचरे के रूप में धरती पर मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 99 प्रतिशत आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो स्वास्थ्य मानकों पर खरी नहीं उतरती है। वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की असमय मृत्यु होती है। भारत में भी लाखों लोग प्रदूषित वायु के कारण श्वसन, हृदय और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। जल प्रदूषण की स्थिति भी चिंताजनक है। देश के अनेक नदी निगरानी केंद्रों पर जल गुणवत्ता मानकों से नीचे पाई गई है, जिससे मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट

वॉच के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया ने हर मिनट में लगभग 10 फुटबॉल मैदान के बराबर वन क्षेत्र को खोया है। भारत का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21.71 प्रतिशत है। शहरीकरण, सडक़ निर्माण, खनन और अन्य विकास गतिविधियों के कारण वनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता प्रभावित हो रही है और प्राकृतिक संतुलन कमजोर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। बादल फटना, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और अनियमित वर्षा जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी जन-धन हानि हो चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान जब मानवीय गतिविधियां सीमित हुई, तब प्रकृति में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिला था। कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहतर हुई, नदियों का जल अधिक स्वच्छ दिखाई दिया और वन्यजीवों की गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रकृति में स्वयं को पुनर्जीवित करने की अद्भुत क्षमता है, आवश्यकता केवल उसे पर्याप्त अवसर देने की है। समाधान भी हमारे दैनिक जीवन में ही छिपा हुआ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए, तो बड़ा परिवर्तन संभव है। सिंगल-यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के थैले अपनाना, स्टील की बोतलों का उपयोग करना, जल और बिजली की बचत करना तथा कचरे का पृथक्करण करना, सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं।

देश के लिए रोल मॉडल बना यूपी का पंचायती राज विभाग, 3 अभिनव पहले राष्ट्रीय संकलन में शामिल

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विभाग ग्रामीण सुशासन और डिजिटल क्रांति की नई परिभाषा लिख रहा है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ पहलों पर जारी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संकलन *नेशनल कंपेंडियम* में उत्तर प्रदेश की तीन अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिनव पहलों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश जमीनी स्तर पर तकनीकी बदलाव, ग्रामीण सुरक्षा और राजकोषीय हस्तांतरण में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक के दम पर देश का रोल मॉडल बना दिया है। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण सचिवालयों को सीधे शासन की मुख्यधारा से जोड़कर न केवल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया

है, बल्कि अंतिम पायदान पर बैठे ग्रामीण के लिए सरकारी सेवाओं को उनके दरवाजे पर सुलभ कर दिया है। एआई-आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल- ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह क्रियाशील और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अनूठे डिजिटल सिस्टम को लागू किया है। इसके तहत वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सचिवालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकग्निशन और जियो-फेंसिंग तकनीक लागू की गई है। ग्राम पंचायतों के किसी भी विकास कार्य का डिजिटल भुगतान तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान या पंचायत सहायक की डिजिटल उपस्थिति सीधे ग्राम सचिवालय परिसर से दर्ज न हो। इससे वित्तीय गबन की संभावनाएं समाप्त हुई हैं और पारदर्शिता को नया आयाम मिला है। ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्रों की स्थापना : ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालयों को ही आधार नामांकन और अपडेट केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। ग्रामीणों को अब अपने आधार कार्ड में सुधार या नए नामांकन के लिए तहसील या शहरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। पंचायती राज निदेशालय ने इसके लिए यूआईडीएआई से आधिकारिक रजिस्ट्रार के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा तो बच ही रहा है, साथ ही पंचायत सहायकों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल रहे हैं। पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए राज्य में डिजिटल राजस्व संग्रह प्रणाली को कड़ाई से लागू किया गया है। मांग सृजन से लेकर तत्काल बैंक मिलान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। पारदर्शी व्यवस्था के चलते टैक्स चोरी रुकी है और पंचायतों की खुद की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रही हैं और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प का जीवंत उदाहरण है, जिसमें वे उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और साधन-संपन्न बनाने की बात करते हैं। विभाग द्वारा लागू की गई ये तीनों डिजिटल प्रणालियां आज देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप हम *डिजिटल पंचायत - सशक्त पंचायत* के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हमारी तीन योजनाओं को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्वीकार करना यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश देश में सुशासन की नई परिभाषा लिख रहा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि हम *विकसित पंचायत से विकसित भारत* के संकल्प को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार के नेशनल कंपोडियम में उत्तर प्रदेश की तीन पहलों को जगह मिलना हमारे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिन-रात की मेहनत की स्वीकृति है। यह राष्ट्रीय सम्मान उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शासन व्यवस्था में आए एक क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करता है, जो आने वाले समय में देश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में मील का पत्थर साबित होगा।

बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल में भीषण आग, पांच लोगों की मौत

मुजफ्फरपुर (हिंस)। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग की घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। आग तड़के करीब 3 बजे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी। इसके बाद देखते ही देखते पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया। इससे अस्पताल परिसर के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। इससे आईसीयू वार्ड में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ और आग तेजी से फैल गई। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घटना के बाद करीब 12 बड़ी-छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। अस्पताल को खाली कराया गया है। अस्पताल के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर के औराई निवासी शशांक कुमार, मोतीपुर निवासी गीता देवी, शिवहर जिले के तरियानी निवासी उदय कुमार, कृष्ण नंदन और चंचला कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना में झुलसे कई लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दु:खद है। शोक-संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार के लिए सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दु:खद और हृदयविदारक है।

पंजाब के पांच मंदिरों और पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां अलर्ट

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के पांच प्रसिद्ध मंदिरों और चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। धमकी भरी ई-मेल में दावा किया गया कि दोपहर 1-11 बजे से 3-11 बजे के बीच धमाके किए जाएंगे। ई-मेल में अमृतसर के दुर्ग्याणा मंदिर, पठानकोट के मुक्तेश्वर मंदिर, जालंधर के देवी तालाब मंदिर, बठिंडा के मैसरखाना मंदिर और पटियाला के काली देवी मंदिर का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ई-मेल मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। संबंधित मंदिरों और सचिवालय परिसर के आसपास विस्तृत तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि शुरुआती जांच में किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस और साइबर सेल की टीमें धमकी भरी ई-मेल की जांच कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि ई-मेल किस आईडी से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ई-मेल में 6 जून, 1984 को श्री दरबार साहिब पर हुई सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए बदले की बात भी लिखी गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल की सत्यता और इसके स्रोत की जांच में जुटी हुई हैं। सभी संबंधित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर बिजनौर में हाई वोल्टेज सियासत

बिजनौर (हिंस)। आजाद समाज पार्टी की प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले गुरुवार को जिले में राजनीतिक माहौल गरमा गया। जिला प्रशासन ने सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनके धामपुर स्थित निवास पर सवेरे ही नजरबंद कर दिया था, कई घंटे चली वार्ता के बाद चन्द्रशेखर को बिजनौर में सभा करने की बात पर सहमति बनी जिसके बाद सासंद चन्द्रशेखर आजाद नहटौर होते हुए बिजनौर जनसभा स्थल इन्दिरा बाल भवन पर काफिले के साथ पहुंचे 7 उन्होंने सभा की अनुमति न मिलने पर सरकार को जमकर कोसा। गौरतलब है कि आसपा द्वारा पदयात्रा के रूप में पदयात्रा निकालने की घोषणा कई दिनों पहले की गई थी पर जिला प्रशासन ने पदयात्रा की अनुमति प्रदान नहीं की थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद के बिजनौर पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। वहीं आजाद समाज पार्टी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी की।

राज्यसभा चुनाव : भाजपा ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

जयपुर (हिंस)। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री अलका गुर्जर को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। विधानसभा में वर्तमान संख्या बल के आधार पर भाजपा दो सीटों पर जीत की स्थिति में है, जबकि तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक रहने की संभावना है। ऐसे में भाजपा ने अपने दोनों संभावित विजयी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। भाजपा द्वारा अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाए जाने को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने इस निर्णय के जरिए पूर्वी राजस्थान

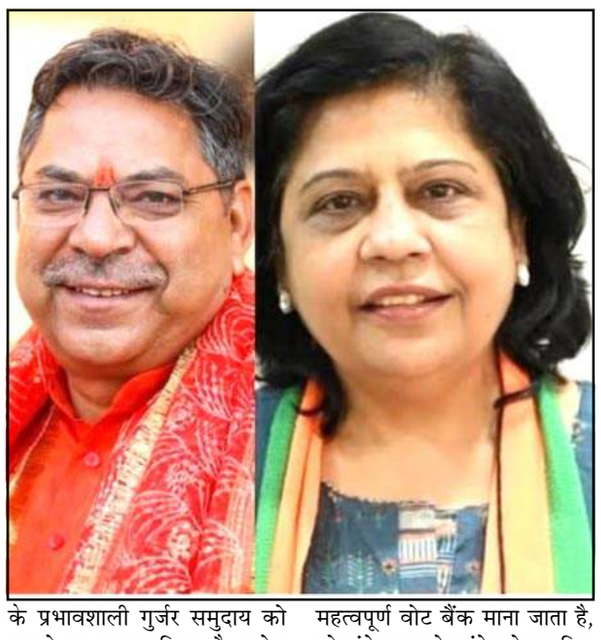

के प्रभावशाली गुर्जर समुदाय को साधने का प्रयास किया है। प्रदेश की राजनीति में गुर्जर समाज को महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है, जो लंबे समय से कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रभाव के कारण कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अलका गुर्जर को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने इस सामाजिक समीकरण में अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रही हैं तथा विधायक और मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। वहीं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी ने संगठन और राजनीतिक अनुभव को भी महत्व दिया है। पूनिया प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते ये तीनों सीटें रिक्त हो रही हैं।

भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

यमुनानगर (हिंस)। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के आह्वान पर वीरवार को किसानों ने भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी किसान जगाधरी अनाज मंडी परिसर में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इसका असर देश के कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे कारोबारियों तथा रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है। इस दौरान विरोध स्वरूप केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाकियू के जिला अध्यक्ष संजू ने कहा कि भारत में अधिकांश कृषक छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं, जबकि अमेरिका में कृषि बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता के बल पर संचालित होती है।

ओबीसी अभ्यर्थियों की भर्ती आयु सीमा में छूट मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज (हिंस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ओबीसी अभ्यर्थियों सतेंद्र कुमार व एक अन्य की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचियों की शिकायत है कि 18 जून 2026 को संबंधित भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल बंद हो जाएगा और वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है, जबकि याची क्रमश: 2024 और 2021 में यह आयु सीमा पार कर चुके हैं। याचियों का तर्क है कि पुराने विनियम 9(टू) में प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के आधार पर पात्र माने जाएंगे। यह प्रावधान 30 सितम्बर 2025 से हटा दिया गया। अंतिम विज्ञापन 2019 में जारी हुआ था।

हरियाणा सरकार ने 23 खिलाड़ियों को दी कोच की नौकरी

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में नए ओलंपिक चैंपियन गढ़ने की रणनीति तैयार की है। मिशन ओलंपिक-2036 के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को तराश जाएगा। इसी कड़ी में खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 23 खिलाड़ियों को कोच के नियुक्ति पत्र सौंपे।पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वर्ष 2036 के ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के माध्यम से 36 पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें नवनियुक्त कोचों की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी देते हुए गांवों और कस्बों में छिपी प्रतिभाओं को तराशकर ओलंपिक, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप स्तर के खिलाड़ी तैयार करने का आह्वान किया। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की खेल नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को डी ग्रुप की नौकरियों में 10 प्रतिशत तथा सी ग्रुप की नौकरियों में

3 प्रतिशत खेल कोटा प्रदान किया जाता है। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में खेल प्रतिभा स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यहां का युवा केवल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए मैदान में उतरता है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की *पदक लाओ, पद पाओ* नीति का उद्देश्य खिलाड़ियों को भविष्य की चिंता से मुक्त करना है। सरकार खिलाड़ियों को केवल सम्मानित ही नहीं करती, बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य की भी गारंटी देती है, ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर खेल विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, अतिरिक्त निदेशक अश्वनी मलिक सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खेल मंत्री ने कहा कि कोच खिलाड़ियों को तराशकर हीरा बनाने का कार्य करते हैं। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के इस दौर में कोचों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने नवनियुक्त कोचों से आग्रह किया कि वे गांवों और कस्बों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों के लिए तैयार करें।

भारत-पाक सीमा से सटे पठानकोट क्षेत्र में पुलिस-बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन

चंडीगढ़ (हिंस)। भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्रों में गुरुवार को जिला पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सीमावर्ती दरियाओं के किनारों, जंगलों और अन्य सुनसान क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा कई लोगों से पूछताछ भी की गई और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी गई। जिला पुलिस प्रमुख एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया यह नियमित सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना है। यह अभियान थाना नरोट जैमल सिंह के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर कुलदीप राज के नेतृत्व में चलाया गया, जबकि डीएसपी ऑपरेशन गुरबख्श सिंह बाजवा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती गांवों में कई संदिग्ध ठिकानों की गहन तलाशी ली। डीएसपी गुरबख्श सिंह बाजवा ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख के निर्देशों के अनुसार लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय

पर ऐसे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने या मकान किराए पर देने से पहले उसकी पूरी पहचान संबंधी जानकारी पुलिस के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों तक पहुंचना आसान हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी को अपने आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजेगा भारत का गौरव 10 जून को होगा 13वां भारत गौरव अवार्ड समारोह

जयपुर (हिंस)। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के योगदान को सम्मानित करने वाला प्रतिष्ठित भारत गौरव अवार्ड इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आयोजित होगा। संस्कृति युवा संस्था की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का 13वां संस्करण आगामी 10 जून 2026 को मेलबर्न स्थित पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विश्व की 25 विशिष्ट विभूतियों को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि भारत गौरव अवार्ड विश्व भर में रह रहे भारतीयों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन चुका है। इससे पहले इसका आयोजन ब्रिटिश संसद (लंदन), फ्रांस की सीनेट, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) तथा दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जा चुका है। इस समारोह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड, थाईलैंड और हांगकांग सहित 18 देशों से भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि और प्रवासी भारतीय भाग लेंगे। आयोजन के माध्यम से वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर

लाकर सांस्कृतिक सहयोग, नवाचार, नेतृत्व और भारत के भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका पर सार्थक संवाद किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह से जुड़कर प्रवासी भारतीयों और सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम संयोजक सुनील खेतपालिया ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथियों में मेहंदीपुर बालाजी धाम के अध्यक्ष महंत डॉ. नरेश पुरी महाराज, विक्टोरिया सरकार के पर्यावरण मंत्री स्टीव डिमोपोलोस, विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन की अध्यक्ष विवियन (विव) गुयेन एएम, विक्टोरियन संसद के सांसद मेंग हेंग टाक तथा महाकुंभ के मुख्य सलाहकार राकेश के शुक्ला शामिल होंगे।

रन फॉर एनवायरमेंट जागरूकता दौड़ का आयोजन प्रतिभागियों को किया गया पौधों का नि:शुल्क वितरण

बीकानेर (हिंस)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा गुरुवार को वंदे गंगा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत *रन फॉर एनवायरमेंट* का आयोजन किया गया। *रन फॉर एनवायरमेंट* जागरूकता दौड़ को हरी झंडी सुबह करीब साढ़े सात बजे मुख्य वन संरक्षक हनुमानाराम, निगम कमिश्नर सिद्धार्थ पलानीचामी, एसडीएम बीकानेर आईएएस महिमा कसाना, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा व बीकानेर रन क्लब के ईशान शर्मा ने संयुक्त रूप से दिखाई। रन का आयोजन उपवन संरक्षक कार्यालय पब्लिक पार्क से कलेक्ट्रेट होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय, म्यूजियम सर्किल से

सर्किट हाउस होते हुए पब्लिक पार्क उपवन संरक्षक कार्यालय तक किया गया। रन से पहले उपवन संरक्षक कार्यालय परिसर में प्रतिभागियों को मुख्य वन संरक्षक श्री हनुमानाराम ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता तथा पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा बीकानेर रन क्लब एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से किया गया। उप वन संरक्षक जी वेंकटेश ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने, वर्षा जल के संरक्षण तथा आमजन में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता तथा पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करना था। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली तथा हरित विकास से जुड़े संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम के समापन पर वन विभाग द्वारा प्रतिभागियों एवं आमजन को नि:शुल्क पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को अधिकाधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने की सतत प्रक्रिया है। प्रतिभागियों ने भी पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर उप वन संरक्षक वन्य जीव संदीप छालानी, सहायक वन संरक्षक सत्यपाल सिंह, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहायक अभियंता गिरीश व्यास, कनिष्ठ अभियंता ज्योति मेव, राधेश्याम स्वामी, वन विभाग के रेंजर साऊथ महेश जाखड़, उत्तर रेंज के रेंजर महावीर रुहिल, वनपाल, सहायक वनपाल, वनरक्षक समेत बड़ी संख्या वनकर्मी, बड़ी संख्या में बीकानेर रन क्लब के सदस्यों समेत जिले के नागरिकों, विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक संगठनों एवं युवा वर्ग ने इस जन-जागरूकता अभियान में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

एआई से बदल रहा विज्ञापन उद्योग, भारत वैश्विक एडटेक हब बनने की ओर अग्रसर : रिपोर्ट

नई दिल्ली

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वैश्विक विज्ञापन उद्योग को तेजी से नया रुप दे रहा है और भारत को दुनिया की अग्रणी एडटेक (विज्ञापन प्रौद्योगिकी) कंपनियों का केंद्र बनने की राह पर अग्रसर कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई विज्ञापनों को अधिक स्वचालित, डेटा-आधारित और परिणाम-केंद्रित माडल की ओर ले जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1 ट्रिलियन डालर से अधिक के वैश्विक विज्ञापन बाजार में एआई अब मीडिया खरीद, क्रिएटिव कंटेंट निर्माण, प्रदर्शन मापन, ई-कामर्स और ग्राहकों को लक्षित करने सहित विज्ञापन उद्योग की करीब हर प्रमुख प्रक्रिया को क्रांतिकारी ढंग से बदल रहा है। वैश्विक विज्ञापन खर्च का करीब 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा अब डिजिटल माध्यमों का है, जिसमें से 80 से 85 प्रतिशत डिजिटल विज्ञापन पहले से ही प्रोग्रामैटिक तकनीक के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

भारत की मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीकी कौशल इस बदलाव का आधार बन रहा है। देश में प्रति वर्ष करीब 27 लाख इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी छात्र नामांकित होते हैं, साथ ही 2 करोड़ से 2.4 करोड़ गिटहब डेवलपर्स और करीब 1,900 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) मौजूद हैं।

यह विशाल प्रतिभा पूल एआई-आधारित उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि भारत का डिजिटल विज्ञापन बाजार 2025 में लगभग 21 अरब डालर से बढ़कर 2030 तक 33 अरब डालर से 42 अरब डालर के बीच पहुंच सकता है, जो एआई आधारित नवाचार को और गति देगा। बाजार जानकार ने इस बदलाव पर जोर देकर कहा, एआई विज्ञापन उद्योग में केवल एक नई परत नहीं जोड़ रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। उन्होंने बताया कि मशीन लर्निंग-आधारित बोली प्रणाली, आइडेंटिटी ग्राफ और एजेंटिक विज्ञापन ढांचे जैसी तकनीकों के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग क्षमता भारत ने पिछले तीन दशकों में विकसित की है।

न्यूज ब्रीफ

केंद्र सरकार ने एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाए 4,300 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड में बिक्री पेशकश (ओएफएस) के आखिरी दिन बुधवार को अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 4,300 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 60.27 करोड़ शेयरों के बिक्री पेशकश (ओएफएस) के मुकाबले कुल 151.33 करोड़ शेयरों के लिए बोली प्राप्त हुई। इस ओएफएस में सरकार की तीन फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश शामिल थी, जबकि तीन फीसदी ग्रीन शू विकल्प यानी अतिरिक्त बोली आने पर उसे अपने पास रखने का विकल्प रखा गया था। सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह एनएचपीसी लिमिटेड में छह फीसदी तक की हिस्सेदारी आफर फार सेल ओएफएस के जरिए बेचेगी। इसके लिए न्यूनतम मूल्य ब्रिकी मूल्य 71 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का यह तीसरा ओएफएस था। पिछले हफ्ते सरकार ने ओएफस के जरिए कोल इंडिया में 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 5,542 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, मई में उसने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में 8.08 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 2,266 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस तरह कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक विनिवेश से सरकार को मिली रकम 7,808 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार 33,837 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा है ।

एसबीआई कार्ड का फैसला, फोनपे क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पाइंट्स में होगी कटौती

नई दिल्ली। एसबीआई कार्ड ने अपने फोनपे एसबीआई क्रेडिट पर्पल और सलेक्ट ब्लैक

कार्डधारकों के लिए रिवार्ड पाइंट्स सिस्टम में अहम बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, जिसके तहत ग्राहकों को विभिन्न खर्चों पर मिलने वाले रिवार्ड पाइंट्स में कटौती या कुछ कैटेगरी में पूरी तरह से समाप्ति का सामना करना पड़ेगा। इन बदलावों का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, आनलाइन शापिंग और अन्य खर्चों पर रिवार्ड पाइंट्स कमाते हैं। पर्पल कार्डधारकों के लिए फोनपे खर्चों पर मासिक रिवार्ड पाइंट्स की सीमा घटाई गई है। अब बीमा संबंधी खर्चों पर अधिकतम 250 पाइंट्स और अन्य फोनपे खर्चों पर 750 पाइंट्स ही मिलेंगे। इसके अलावा, आनलाइन शापिंग पर मिलने वाले कुल पाइंट्स को भी 1,000 से घटाकर 750 कर दिया गया है। इसी तरह सलेक्ट ब्लैक कार्डधारकों के लिए भी नियम बदले हैं। फोनपे खर्चों पर पहले जहां 2,000 पाइंट्स मिलते थे, अब बीमा पर 500 और अन्य फोनपे ट्रांजैक्शन्स पर 1,500 पाइंट्स की सीमा तय की गई है। आनलाइन खर्चों पर मिलने वाले पाइंट्स को भी 2,000 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है।

केरल पर गंभीर वित्तीय संकट, कर्ज 5 लाख करोड़ पार

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक गंभीर वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (श्वेत पत्र) पेश की, जिसमें राज्य पर 5.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल कर्ज और लगभग 49,000 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान उजागर हुए हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार यह रिपोर्ट बताती है कि बढ़ते कर्ज और देनदारियों के कारण विकास व बुनियादी ढांचे में निवेश की क्षमता सीमित हो गई है। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 77 फीसदी हिस्सा खर्च कर देते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का मात्र 1.3 फीसदी है, जो देश में सबसे कम है। रिपोर्ट ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के लगभग 21,000 करोड़ रुपये के ऋण पर भी चिंता जताई है, जिसे अंततः राज्य सरकार को ही चुकाना होगा। यह गंभीर वित्तीय चुनौती राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को बाधित कर रही है और दैनिक नकदी जरूरतों के लिए आरबीआई की आपात उधारी पर निर्भरता बढ़ा रही है ।

सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च हुआ वाह केमिकल्स का आईपीओ, आठ जून तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का उत्पादन करने वाली कंपनी वाह केमिकल्स का 13.45 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में आठ जून तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद नौ जून को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 10 जून को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 11 जून को बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 60 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है, जबकि लाट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,40,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 22.42 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 1.14 लाख शेयर मार्केट मेकर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 47.46 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए भी 47.46 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.08 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए मारवाड़ी चंदाराणा इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं मानसी शेयर एंड स्टाक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है। वाह केमिकल्स की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 2.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 5.09 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 23.75 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 43.19 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में मामूली बढ़ोतरी हुई।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी पर 11.25 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 11.31 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस दौरान कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में ये 6.87 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2025-26 में बढ़ कर 14.92 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर भी बढ़त हासिल करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में ये 1.50 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2025-26 में बढ़ कर 8.85 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2024-25 में 4.68 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2025-26 में बढ़ कर 8.23 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

वैश्विक दबाव से महंगी हुई दवाएं, मरीजों पर बढ़ा बोझ, नए स्टाक 8 से 17 फीसदी तक महंगे

मुंबई। वैश्विक महंगाई और बाधित सप्लाई चेन का असर अब आम आदमी की सेहत पर भी दिखने लगा है। कच्चे माल, पैकेजिंग व समुद्री परिवहन लागत में उछाल से दवा कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ी है। इसका सीधा असर नए दवा स्टाक पर पड़ा है, जहां कई आवश्यक दवाओं की कीमतें 8 से 17 फीसदी तक बढ़ गई हैं, जिससे मरीजों के मासिक खर्च में बढ़ोतरी की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन जैसी दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट और पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में 40 से 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, दवाओं की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और एल्युमीनियम भी महंगे हुए हैं। इस वृद्धि का असर पुराने स्टाक पर सीमित है, लेकिन नए बैच की दवाएं अब अधिक कीमत पर मिल रही हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक। फार्मा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे माल और परिवहन लागत में जल्द राहत नहीं मिली, तो भविष्य में कई और दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी।

वेदांता ने पांच वर्षों में 25 लाख टन कार्बन उत्सर्जन किया कम

नई दिल्ली

वेदांता समूह के लौह अयस्क खनन और इस्पात कारोबार ने पिछले पांच वर्षों में अपनी स्थिरता पहलों के माध्यम से लगभग 25 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी या अवशोषण कर पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कदम भारी उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों और राष्ट्रीय व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

कंपनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कम-कार्बन भविष्य के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वेदांता के प्रयासों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रमुख है, जहां विद्युत चालित यात्री वाहन, लोडर और फोर्कलिफ्ट के इस्तेमाल से प्रति वर्ष लगभग 800 किलोलीटर डीजल की बचत हुई।

सतत परिवहन व्यवस्था के तहत जलमार्ग पोत संचालन ने 2.1 लाख ट्रक यात्राओं को कम करके 1.08 करोड़ लीटर डीजल और लगभग 28,900 टन कार्बन डाइआक्साइड की बचत की। ऊर्जा दक्षता में

नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सघन वनीकरण से हासिल की उपलब्धि

अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित की गई, जिससे 2.4 मिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन से बचाव हुआ।

पर्यावरण पुनर्स्थापन के तहत, गोवा की पुनर्वास खदान सहित अन्य स्थानों पर कुल 11 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो हर साल हजारों टन सीओ2 अवशोषित करते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में एलपीजी के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग सालाना लगभग 1,500 टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करेगा। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि टिकाऊ भविष्य के लिए उद्योगों को ऊर्जा उपयोग, परिवहन और पर्यावरण के साथ अपने संबंधों पर नए सिरे से विचार करना होगा।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बना दबाव

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। वहीं, एशियाई बाजार में भी आमतौर पर कमजोरी का रुख बना हुआ है।

पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव और फाइनेंशियल तथा टेक स्टाक्स में हुई जोरदार बिकवाली के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 620.72 अंक यानी 1.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 50,687.07 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,553.68 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक

239.93 अंक यानी 0.89 प्रतिशत टूट कर 26,853.98 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.08 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 50,728.46 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,332.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,150.42 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 328.23 अंक यानी 1.32 प्रतिशत लुढ़क कर 24,795.94 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में भी आमतौर पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। एशिया के नौ बाजार में से आठ के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि एक सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में बना हुआ है। एशियाई बाजार में इकलौता सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,597.04 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.06 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,318 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.43 प्रतिशत टूट कर 4,066.56 अंक के स्तर तक गिर गया है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 214.35 अंक यानी 3.61 प्रतिशत फिसल कर 5,726.72 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 410.21 अंक यानी 1.60 प्रतिशत लुढ़क कर 25,223 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 1,042.13 अंक यानी 1.52 प्रतिशत टूट कर 67,360 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। वहीं स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,071.61 अंक के स्तर पर, ताइवान वेटेड इंडेक्स 473.42 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,985.74 अंक के स्तर पर और कोस्पी इंडेक्स 0.57 प्रतिशत टूट कर 8,751.76 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

पृष्ठ एक का शेष

राज्य में आज...

कामकाज की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस मंत्रिमंडल गठन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि नए कार्यकाल में सरकार की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संकेत मिल सकें।

ममता ही रहेंगी सुप्रीम ...

बात की। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। वह सिर्फ एक सलाहकार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी पूरी तरह उनके नेतृत्व में काम करे। दरअसल, यह विवाद बुधवार को ऋतब्रत बनर्जी के एक प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ। ऋतब्रत ने सुझाव दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को पुनर्गठित विधायक दल का मुख्य सलाहकार बनाया जाना चाहिए। गुलशन मल्लिक ने इसी पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तो हमें सोचना होगा कि हम इस गुट में रहें या नहीं। इस बयान ने विद्रोह के सबसे बड़े अंतर्विरोध को सामने ला दिया है। यह पूरा विद्रोह ममता बनर्जी के नाम पर ही किया गया है। लेकिन अब इसी बात पर बहस छिड़ गई है कि खुद ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी? विद्रोह करने वाले 58 विधायकों ने शुरू से ही एक बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। वे केवल ममता के भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ हैं। सीतई से एक और बागी विधायक संगीता रॉय बसुनिया ने भी मल्लिक की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारी सुप्रीम लीडर हैं और हमेशा रहेंगी। वह सलाहकार नहीं हो सकतीं। वह हमारी नेता हैं। ऋतब्रत ने दरअसल ममता को सलाहकार बनाने का प्रस्ताव एक रणनीति के तहत दिया था। वह विद्रोह के राजनीतिक असर को कम करना चाहते थे। वह तृणमूल के आम कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि यह आंदोलन पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ नहीं है। लेकिन गुरुवार को आए बयानों ने साफ कर दिया कि बागी खेमे का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के अधिकारों को कम करने वाले किसी भी फॉर्मूले से बेहद असहज है। मालूम हो कि ममता बनर्जी ने 1998 में इस पार्टी की स्थापना की थी। वह पार्टी को विपक्ष के हाशिए से उठाकर 2011 में सत्ता तक लेकर आईं। विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में भी बागियों ने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे विधायक दल के कामकाज पर अभिषेक बनर्जी के अधिकार को अब स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुवार की इस बैठक में बागी विधायकों ने केवल नेतृत्व पर ही बात नहीं की। उन्होंने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं पर भी चर्चा की। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामले और जिलों की प्रशासनिक चिंताएं शामिल थीं। गुलशन मल्लिक ने बताया कि इन मुद्दों को राज्य सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उठाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

रास चुनाव : भाजपा ने ...

सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। भाजपा की इस सूची में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका के चलते राज्यसभा भेजने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं राजस्थान में नए चेहरों को मौका देकर पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है। राज्यसभा चुनाव में इन उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा इन राज्यों में मजबूत स्थिति में है।

एपीडब्ल्यू ने असम के ...

गया था। शिकायत में विशेष रूप से पूर्व स्पीकर दैमारी के दो विशेष कर्तव्य अधिकारियों (ओएसडी), सौमेन बरुआ और अंतिममरा देवरा चेउरागी, पूर्व विधानसभा सचिव दुलाल पेगु, ठेकेदार फर्म नोव कंप्यूटिंग और ठेकेदारों माधव डेका, सुंदर नाथ मिश्रा और गौतम बोड़ो, आदि की भूमिकाओं की जांच की मांग की गई है। एपीडब्ल्यू ने विधानसभा परिसर के भीतर की गई गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें बुनियादी ढांचे में संशोधन कार्य, आईटी उपकरणों की खरीद, ऑडियो-विजुअल सिस्टम की स्थापना, भवन प्रबंधन अनुबंध, रखरखाव सेवाएं, मानव संसाधन की नियुक्ति और विभिन्न अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। संगठन ने इन परियोजनाओं से संबंधित फाइलों, बिलों, खरीद रिकॉर्ड और भुगतान अनुमोदनों की विस्तृत जांच की मांग की है। इस ज्ञापन में नोव कंप्यूटिंग और अन्य फर्मों को दिए गए अनुबंधों, कथित तौर पर बढ़ी हुई कीमतों पर उपकरणों की खरीद और प्रौद्योगिकी से संबंधित और रखरखाव सेवाओं पर किए गए व्यय को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। इसके अतिरिक्त, एपीडब्ल्यू ने विधानसभा के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर की गई नियुक्तियों, संविदात्मक समझौतों और विदेशी यात्राओं के साथ-साथ नए विधानसभा भवन से संबंधित अग्नि सुरक्षा संबंधी टिप्पणियों के रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। एपीडब्ल्यू ने चेतावनी दी है कि यदि विधानसभा अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो वह इस मामले को भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के समक्ष ले जाएगी और अदालती कार्यवाही शुरू करेगी। संगठन ने कहा कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अनियमितता और बड़े पैमाने पर लूटपाट के इन कथित कृत्यों में मुख्य आरोपी पर भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के समक्ष मुकदमा चलाया जाएगा, और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले सभी मामलों को अदालतों के समक्ष ले जाया जाएगा।

अहमदाबाद मे गंदा ...

बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और मेयर से स्थिति को जाना है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आकांक्षा अपार्टमेंट में रहने वाले 500 से ज्यादा लोग बीमारियों का शिकार हो गए हैं। खासकर पिछले तीन दिनों से कुछ परिवारों के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता फैल गई है। घाटलोडिया विधानसभा के नॉर्थ वेस्ट जोन के गोटा वार्ड की कुछ सोसाइटियों में डायरिया और उल्टी की स्थिति के बारे में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और एएमसी मेयर से बात की और हालात का जायजा लिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की 40 हेल्थ टीमों द्वारा घर-घर सर्वे और बीमारी की रोकथाम का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एएमसी द्वारा अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई और टैंकरों के जरिए सोसाइटियों को पीने का साफ पानी देने का काम भी किया गया।

बीसीसीआई बैठक में होगा सूर्यकुमार की कप्तानी पर फैसला, वैभव को शामिल करने पर भी होगा विचार

मुम्बई

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चयन समित की बैठक इस शनिवार को होने जा रही है। इसमें अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कप्तान सूर्यकुमार यादव के भविष्य को लेकर फैसला करेंगी। इस बैठक में तय होगा कि सूर्या आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों के अलावा इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों में कप्तान रहेंगे या नहीं। इसके अलावा इसी बैठक में सितंबर में जापान में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीमों का चयन किया जाएगा। इस बैठम में 15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टी20 टीम में शामिल किये जाने पर भी बात होगी।

जहां तक सूर्यकुमार की कप्तानी की बात है। पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। आईपीएल में भी वह रनों के लिए जूझते दिखे। ये सही है कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप जीतकर उसे बरकरार रखा पर इसमें उनका योगदान बेहद कम रहा। सूर्यकुमार की कमजोर बल्लेबाजी लगातार निशाने पर रही। का आईपीएल 2026 में, उन्होंने 13 पारियों में केवल 270 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 20.76 और स्ट्राइक रेट 147.54 का रहा है। वहीं टी20 विश्व कप में वह नौ पारियों में 242 रन बना पाये। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 136.72 तक पहुंच गया। सूर्यकुमार का नाम एशियन गेम्स के लिए घोषित 30 संभावित नामों में भी शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या चयनकर्ता आने वाली कुछ सीरीज के लिए किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी का मौका देंगे, या सूर्यकुमार को अनुभव के लिए केवल एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में बनाए रखा जाएगा, खासकर जब उन्होंने 2028 ओलंपिक में खेलने की इच्छा जताई है। दूसरी ओर, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले पूरे आईपीएल सत्र में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। वैभव की क्वालीफायर मुकाबलों में खेली गयी पारी से भी चयनकर्ता काफी प्रभावित हुए हैं। अब देखना होगा कि उन्हें अंतिम ग्यारह में कैसे शामिल किया जाए क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन अच्छे प्रदर्शन के कारण पहले से ही टीम में शामिल हैं! वहीं मध्यक्रम में जगह बनाने के लिए, श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार दोनों ही मजबूत दावेदार हैं। पिछले दो आईपीएल सीजन में दोनों ने अपनी टीमों की शानदार कप्तानी की है। पाटीदार ने इस सत्र में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जिताया है जबकि श्रेयस ने 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था।

न्यूज ब्रीफ

आईसीसी प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश दौरे में शासन और चुनावी मामलों पर हितधारकों से की चर्चा

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से जुड़े प्रशासनिक और चुनावी मामलों में हुए हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा करना था। इस प्रतिनिधिमंडल में आईसीसी बोर्ड निदेशक डा. मोहम्मद एएस मूसाजी (क्रिकेट साउथ अफ्रीका) और तावेंगा मुकुहलानी (जिम्बाब्वे क्रिकेट) शामिल थे। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कर स्थिति का आकलन किया। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट और टिप्पणियां उचित समय पर आईसीसी बोर्ड को सौंपेगा। साथ ही आईसीसी ने यह भी कहा कि इस मामले पर प्रतिनिधिमंडल की ओर से कोई सार्वजनिक या मीडिया टिप्पणी नहीं की जाएगी। आईसीसी के अनुसार दौरे को लेकर मीडिया में चल रही रिपोर्टें, चर्चाएं या दावे केवल अटकलें हैं और उन्हें आईसीसी का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए।

फ्रेंच ओपनः चोटिल बेरेटिनी के हटने से अर्नाल्डी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे

पेरिस। फ्रेंच ओपन 2026 में इटली के मातेओ अर्नाल्डी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल खेलना सुनिश्चित कर लिया। बुधवार को खेले गए क्वार्टरफाइनल में उन्हें हमवतन मातेओ बेरेटिनी के चोट के कारण मुकाबले से हटने का फायदा मिला। मुकाबले के समय अर्नाल्डी 7-5, 5-2 से आगे चल रहे थे, तभी बेरेटिनी ने चोट के चलते मैच छोड़ने का फैसला किया। दूसरे सेट के शुरुआती खेलों के दौरान उन्हें कूल्हे में परेशानी महसूस हुई और उन्होंने चिकित्सकीय सहायता भी ली। इसके बाद विश्राम के दौरान अपने सहयोगी दल की सलाह पर उन्होंने मुकाबले से नाम वापस ले लिया। विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद अर्नाल्डी ने इस टूर्नामेंट में शानदार संघर्ष दिखाया है। क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने के दौरान उन्होंने कोर्ट पर कुल 17 घंटे 42 मिनट बिताए।अब सेमीफाइनल में उनका सामना एक और इतालवी खिलाड़ी फ्लावियो कोबोली से होगा। इससे यह तय हो गया है कि रविवार को होने वाले पुरुष एकल फाइनल में एक इतालवी खिलाड़ी जरूर पहुंचेगा। विश्व नंबर एक और पिछले वर्ष के उपविजेता यानिक सिनर के शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद इटली के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैच के बाद अर्नाल्डी ने कहा, यह मुश्किल स्थिति है। हम दोनों ने काफी लंबे मुकाबले खेले थे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्तर पर खेलना आसान नहीं था। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि किसी खिलाड़ी का टूर्नामेंट इस तरह खत्म हो। उन्होंने आगे कहा, इटली में टेनिस लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बेरेटिनी जल्दी फिट होकर वापसी करेंगे। घास के कोर्ट का सत्र जल्द शुरू होने वाला है और वह वहां मजबूत खिलाड़ी साबित होंगे।

क्रिकेट में अब भी भ्रष्टाचार और फिक्सिंग जारी, आईपीएल में ऐसा नहीं : ललित मोदी

लंदन। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कहा कि कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग अब भी समाप्त नहीं हुई। ललित मोदी के अनुसार आजकल इसमें इतनी जटिलताएं हैं कि फिक्सिंग का पता लगाना और इसको पकड़न बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने हालांकि कहा कि आईपीएल में ऐसा नहीं है क्योंकि ये इतना फायदेमंद हो गया है कि कोई भी अपने फिक्सिंग कर अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। उन्होंने कहा, क्रिकेट में फिक्सिंग हो रही है। यह अब बहुत ही मुश्किल स्तर पर पहुंच गई है। आईपीएल में ऐसा है या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं जानता। और मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि सच में मुझे जानकारी नहीं है। पर मुझे भरोसा है कि यह हर जगह मौजूद है। मोदी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से मिली धमकियां के कारण ही वह आईपीएल से अलग हुए थे। साथ ही कहा कि कि मैच फिक्सिंग के लिए तैयार नहीं होने पर भी उनके खिलाफ तीन बार हमले के प्रयास किये गये। उन्हें कहा गया था कि अगर वह इस मैच फिक्सिंग का विरोध नहीं करते हैं तो उन्हें मोटी रकम दी जा सकती है पर उन्होंने इस राशि को ठुकरा दिया था। उन्होंने आईपीएल के शुरुआती तीन सालों में फिक्सिंग के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। इससे अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजी नेटवर्क उनसे नाराज हो गए थे। आईपीएल-2 को दक्षिण अफ्रीका ले जाने के उनके फैसले से भी सट्टेबाजों को नुकसान हुआ था हुआ, इसी करण उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई।

कुसल की कप्तानी में श्रीलंका की शानदार शुरुआत

पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 41 रन से हराया

किंगस्टन

श्रीलंका ने वेस्टइंडीज दौरे के पहले एकदिवसीय मुकाबले में बुधवार देर रात दमदार प्रदर्शन करते हुए 41 रन से जीत दर्ज की। कप्तानी में वापसी कर रहे कुसल मेंडिस ने शानदार अर्धशतक जड़ा, जबकि गेंदबाजों ने लक्ष्य का सफल बचाव करते हुए टीम को जीत दिलाई।

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, हालांकि पथुम निसांका को शुरुआती जीवनदान मिला जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। दूसरे छोर पर कुसल मेंडिस ने शुरुआत में समय लिया, लेकिन फिर तेजी से रन बनाते हुए पारी को गति दी।

कुसल ने विशेष रूप से स्पिनर गुडाकेश मोती पर हमला बोला और लगातार बड़े शाट लगाए। उन्होंने 62 गेंदों पर 72 रन की तेज पारी खेली। कुसल और निसांका के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी ने श्रीलंका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। निसांका ने 79 रन बनाए जबकि मध्यक्रम में चरिथ असलंका ने 45 और जनिथ लियानागे ने नाबाद 44 रन जोड़कर टीम को 50 ओवर में 303/7 तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने तेज शुरुआत की। जान कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन रन आउट ने टीम की लय तोड़ दी। इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाया। महीश तीक्षणा ने ग्रीव्स को आउट कर वापसी कराई, जबकि वानिंदु हसरंगा ने अहम विकेट लेकर मध्यक्रम को झटका दिया। कप्तान शाई होप ने संघर्ष करते हुए 56 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला। अंत में दुष्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 49.2 ओवर में 262 रन पर सिमट गई।

संक्षिप्त स्कोर:

श्रीलंका – 303/7 (50 ओवर)
पथुम निसांका 79, कुसल मेंडिस 72; मैथ्यू फोर्ड 2/44

वेस्टइंडीज – 262 (49.2 ओवर)
शाई होप 56; दुष्मंथा चमीरा 4/67, महीश तीक्षणा 2/26

परिणाम: श्रीलंका 41 रन से विजयी।

44 की उम्र में क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट से वापसी कर रही सेरेना

न्यूजर्सी। अमेरिकी की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 44 साल की उम्र में एक बार फिर टेनिस कोर्ट में वापसी करने जा रही हैं। सेरेन ने अपनी अंतिम टूर्नामेंट चार साल पहले 2022 में खेला था यूएस ओपन 2022 में अपना आखिरी पेशेवर एकल मैच खेलने के बाद से ही सेरेना खेल से दूर हैं हालांकि उन्होंने अधिकारिक रुप से संन्यास की घोषणा नहीं की थी और कहा था कि वह बेहतर होने के लिए खेल से दूर हुई है। वहीं अब सेरेना ने 8 जून से लंदन में होने वाले क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट में खेलने की घोषणा की है। ये विंबलडन के लिए अभ्यास टूर्नामेंट माना जाता है। सेरेना की वापसी की घोषणा के बाद से ही उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है। सेरेना के नाम ओपन युग में महिला एकल में रिकार्ड 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। सेरेने ने अमेरिकी ओपन 2022 को अपना अंतिम टूर्नामेंट बताया था, यह कहते हुए कि वह खेल से दूर एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहती हैं। हालांकि, उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की थी जिससे उनकी वापसी की अटकलें हमेशा बनी रहीं। सेरेना अमेरिकी ओपन में तब तीसरे दौर में हार गई थीं हालांकि अब वह एक बार फिर कोर्ट पर वापसी के लिए तैयार हैं जो उनके भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। क्वींस क्लब में अपनी वापसी की घोषणा करते हुए, विलियम्स ने कहा, क्वींस क्लब इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए एकदम सही जगह लगती है। घास के कोर्ट ने मुझे मेरे करियर के कुछ सबसे यादगार पल दिए हैं, और मैं खेल के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर वापस प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्साहित हूं। क्वींस क्लब नामी ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट है जो 8 से 21 जून तक चलेगा। इससे उन्हें 29 जून से शुरू होने वाले विंबलडन के लिए लय हासिल करने का अवसर मिलेगा। यह संभावना है कि सेरेना को टूर्नामेंट में एकल या युगल दोनों के लिए वाइल्ड-कार्ड से प्रवेश मिल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रारूप में खेलना पसंद करती हैं। उनकी अगली योजना में अमरेकी ओपन में वापसी भी शामिल हो सकती है, वहीं विश्व की पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी लिंडसे डेवनपोर्ट का मानना है कि सेरेना का लक्ष्य अमेरिकी ओपन हो सकता है।

सैफ महिला चैम्पियनशिप: भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह, अब बांग्लादेश से होगी भिड़ंत

मडगांव (गोवा)

पांच बार की चैम्पियन भारतीय महिला फुटबाल टीम ने सैफ महिला चैम्पियनशिप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार रात भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना मौजूदा चैम्पियन बांग्लादेश से शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा।

ग्रुप चरण में दो मैचों में 14 गोल करने वाली भारतीय टीम से एकतरफा प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन भूटान ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाते हुए मुकाबले को कड़ा बनाए रखा। लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची भूटान की टीम ने भारतीय आक्रमण को लंबे समय तक रोके रखा।

फीफा रैंकिंग में 69वें स्थान पर मौजूद भारत ने अधिकांश समय गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन पहले हाफ में गोल नहीं कर सका। करिश्मा, सौम्या गुगुलोथ और अबेका सिंह ने मौके बनाए, लेकिन खराब फिनिशिंग और भूटान की गोलकीपर के शानदार प्रदर्शन के कारण मध्यांतर तक स्कोर 0-0 रहा।

भूटान ने भी जवाबी आक्रमण में कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। दूसरे हाफ में लगातार दबाव का फायदा भारत को 60वें मिनट में मिला, जब सनफिदा नोंगरुम ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। यही गोल अंत में निर्णायक साबित हुआ।

इसके बाद मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने मनीषा कल्याण और प्यारी जाक्षा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा, लेकिन भारत बढ़त नहीं बढ़ा सका। दूसरी ओर भूटान ने अंत तक संघर्ष जारी रखा और भारतीय रक्षा पंक्ति को चुनौती देती रही। हालांकि, अतिरिक्त समय तक मुकाबला ले जाने के लिए जरूरी गोल भूटान नहीं कर सकी और भारत ने 1-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत अब 2019 के बाद पहली बार सैफ महिला चैम्पियनशिप का खिताब जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। इससे पहले पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। बांग्लादेश ने 2022 और 2024 संस्करण भी अपने नाम किए थे।

चीन में बॉलीबाल नेशनल लीग

चीन में बॉलीबाल नेशनल लीग में महिलाओं के पूल 3 मैच में चेक गणराज्य के साथ खेलती हुई मेजबान टीम।

फ्रेंच ओपन में कोबोली का कमाल, पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे

पेरिस

इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी फ्लेवियो कोबोली ने फ्रेंच ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल हासिल कर लिया। रोलां गैरो में खेले गए पुरुष एकल क्वार्टरफाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा के चौथी वरीयता प्राप्त फेलिक्स आगर-एलियासिमे को चार सेटों में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। 24 वर्षीय कोबोली ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी की और लगातार तीन सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम परिणाम है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह सप्ताह उनके जीवन का सबसे यादगार सप्ताह बन गया है।

मुकाबले की शुरुआत में तेज हवा के कारण दोनों खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहला सेट हारने के बाद कोर्ट की छत बंद किए जाने के साथ ही कोबोली की लय लौट आई। उन्होंने आक्रामक फोरहैंड और बेहतरीन फुटवर्क के दम पर मैच का रुख पलट दिया।

इस जीत के साथ कोबोली ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में शीर्ष-10 रैंकिंग वाले खिलाड़ी को हराने का कारनामा भी किया। लाइव एटीपी रैंकिंग में वह 14वें स्थान से उछलकर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अब इटली के ही मैटियो बेरेटिनी और मैटियो अर्नाल्डी के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल विजेता से होगा। इससे यह तय हो गया है कि पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में एक इटालियन खिलाड़ी जरूर पहुंचेगा।

कोबोली की इस उपलब्धि ने इटली के टेनिस इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। यह तीसरा अवसर है जब किसी ग्रैंड स्लैम के पुरुष वर्ग में दो इटालियन खिलाड़ी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। साथ ही, पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में पूरी तरह इटालियन पुरुष सेमीफाइनल सुनिश्चित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले आखिरी इटालियन खिलाड़ी एड्रियानो पनाटा थे, जिन्होंने 1976 में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब कोबोली के पास लगभग पांच दशक बाद इटली को फिर से रोलां गैरो का चैंपियन बनाने का अवसर है।

कमिंस अगले 12 महीनों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी बड़े मुकाबलों में उपलब्ध रहेंगे

नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान पैट कमिंस ने उम्मीद जताई है कि वह अगले 12 महीनों में टीम के सभी बड़े मुकाबलों में उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उन्होंने माना कि आस्ट्रेलिया की प्रमुख तेज गेंदबाजी तिकड़ी के लिए पूरे कार्यक्रम में लगातार खेलना आसान नहीं होगा।

पीठ की चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद कमिंस ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी की थी। वापसी के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

कमिंस ने महिला टी-20 विश्व कप 2026 के प्रसारण से जुड़े अमेज़न प्राइम वीडियो के एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी फिटनेस रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य आई है और अब उनका ध्यान टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने पर है। उन्होंने कहा कि अगला लक्ष्य एक दिन में लंबा गेंदबाजी स्पेल करने और अगले दिन फिर उसी स्तर पर खेलने की क्षमता हासिल करना है।

आस्ट्रेलिया के लिए आने वाला एक वर्ष बेहद व्यस्त रहने वाला है, जिसमें टीम अधिकतम 21 टेस्ट मैच खेल सकती है। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखला, दक्षिण अफ्रीका दौरा, भारत दौरा, इंग्लैंड में एशेज श्रृंखला, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मुकाबले, मेलबर्न में 150वीं वर्षगांठ टेस्ट और संभावित विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल शामिल हैं।

कमिंस ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सभी टेस्ट खेलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम में एक ही तेज गेंदबाजी तिकड़ी का बने रहना कठिन होगा। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मैच खेलूं, लेकिन रास्ते में परिस्थितियां बदल सकती हैं। 21 टेस्ट में लगातार वही तीन तेज गेंदबाज खेलें, यह बहुत हैरान करने वाली बात होगी। बीच-बीच में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आस्ट्रेलिया की प्रमुख तेज गेंदबाजी तिकड़ी में कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क और जाश हेजलवुड शामिल हैं। पिछले एशेज सत्र के दौरान चोटों के कारण कई बार टीम को बदलाव करने पड़े थे और उस समय स्काट बोलैंड, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन और ब्रेंडन डागेट जैसे गेंदबाजों ने जिम्मेदारी संभाली थी। कमिंस ने यह भी संकेत दिए कि टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी भागीदारी कम करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में बिग बैश लीग में उनका खेलना पहले से कम संभावित नजर आ रहा है। जाश हेजलवुड की वापसी पर कमिंस ने भरोसा जताते हुए कहा कि चोटों के बावजूद वह नियमित टेस्ट क्रिकेट खेलने में सक्षम हैं। उन्होंने हाल में इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी कर अपनी उपयोगिता साबित की है। कमिंस ने कहा कि गेंदबाजी में लय बहुत मायने रखती है और हेजलवुड को फिर से लगातार क्रिकेट खेलते देखना टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।

कई बिमारियों में कारगार है ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण की मौजूदगी श्वसन तंत्र को सुचारू बनाने में फायदेमंद होती है। साथ ही यह दर्द को कम करने में मदद करता है। एक आधा छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल में सामान मात्रा में शहद मिलाकर, सोने से पहले नियमित रूप से लें। गले में कंपन को कम करने और खर्राटों को रोकने के लिए नियमित रूप से इस उपाय का प्रयोग करें।

धूम्रपान से मुंह की बीमारियों का खतरा क्यों!

सिगरेट पीने से न सिर्फ कुछ जीवाणु मुंह में जमा हो जाते हैं, बल्कि वे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर भी हावी हो जाते हैं, जिसके कारण मुंह संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। ये जीवाणु दांत, हृदय वॉल्व और धमनियों में बायोफिल्म्स का निर्माण करते हैं। बॉयोफिल्म कई सारी सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बनी जटिल संरचना होती है। इसके कारण कई अन्य नई समस्याएं भी पैदा हो जाती है।

डॉक्टर की सलाह के बिना पैरासीटामॉल लेने से हो सकती हैं ये बीमारियां

सिर में मामूली सा दर्द हुआ नहीं कि रीमा ने पैरासीटामॉल की गोली गटक ली। रीमा हीं नहीं बल्कि रीमा की तरह बहुत से लोग ऐसा हीं करते हैं। लोगों को सेल्फ मेडिकेशन एक आसान, सस्ता और कम समय में होने वाला उपाय लगता है। लेकिन कम समय में मिलने वाली राहत जल्द ही स्थायी आदत में तब्दील हो जाती है और शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। माना कि पैरासीटामॉल एक ऐसी दर्दनिवारक दवा है जिसे दर्द होने पर समान्य लोगों के साथ-साथ गर्भवती महिलाएं भी आसानी से ले लेती है। और अधिक नुक्सानदेह ना होने कारण भारतीय मेडीकल दुकानों पर यह दवा बिना डॉक्टर की स्लिप आसानी से ली जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टरी सलाह के बिना मामूली बुखार से परेशान होने पर भी आप पैरासीटामॉल की गोली ले लेते हैं और ऐसा आप कई सालों से करते आ रहे हैं, तो सावधान हो जाये। क्योंकि हर बार मामूली से दर्द या बुखार में पैरासीटामॉल लेना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अधिक इस्तेमाल से शरीर के कई अंगों को नुकसान हो सकता है। आइए जानें बिना डॉक्टर की सलाह के बिना पैरासीटामॉल लेना शरीर के लिए कैसे नुकसानदेह होता है। क्या आपने कभी भी दवा के पैकेट पर लिखा देखा हैं कि ज्यादा मात्रा में पैरासीटामॉल लेना लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। जीं हां डॉक्टरों का कहना है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 3 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामॉल नहीं लेनी चाहिए और अगर किसी कारणवश लेनी भी पड़े तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए।

गर्भवती और बच्चों के लिए नुकसानदेह: आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि गर्भवती के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली पैरासीटामॉल अगर बिना जांच के गर्भवती को दी जाती है तो सुरक्षित समझे जाने वाली पैरासीटामॉल की गोली गर्भ में पल रहे बच्चे के पूर्ण विकास में रुकवाट पैदा कर सकती है। नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार गर्भवती को बिना डॉक्टरी सलाह के पैरासीटामॉल नही लेनी चाहिए।

किडनी पर असर: दर्द निवारक दवा के रूप में पैरासीटामॉल का लंबे समय तक सेवन करना बहुत हानिकारक है। बिना डॉक्टरी सलाह के पीठ दर्द के लिए इसे लेने पर यह लाभ के बजाए नुकसान पहुंचाती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं के अनुसार आस्टियोआर्थराइटिस एवं पीठ दर्द को कम करने के लिए लोग पैरासीटामॉल का इस्तेमाल आसानी से करते हैं, पर इसका किडनी पर असर पड़ता है।

अस्थमा की समस्या: हल्का सा बुखार होने पर ही हम अपने बच्चे को पैरासीटामॉल देने लगते हैं। लेकिन कई शोधों से ये बात साबित हुई है कि 6-7 साल की उम्र में बच्चों को पैरासीटामॉल देने से उनके शरीर में अस्थमा के लक्षणों को बढ़ावा मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि बच्चों को 101.3 एस्न बुखार होने पर ही पैरासीटामॉल देनी चाहिए।

पेट में गैस की समस्या और त्वचा पर एलर्जी : कई मामलों में तो पैरासीटामॉल का अधिक सेवन पेट में गैस की समस्या पैदा कर सकता है। तो अगर आप अपच या पेट में भारीपन से परेशान हैं तो हो सकता है कि ऐसा पैरासीटामॉल के सेवन से हो रहा हो। इसके अलावा कुछ लोगों को पैरासीटामॉल के अधिक सेवन करने से त्वचा पर लाल चकत्ते और एलर्जी हो जाती है, जिसमें खुजली या जलन भी होती है।

लीवर को नुकसान: अगर आप पीलिया या लीवर संबंधी किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना पैरासीटामॉल खाने से लीवर डैमेज हो सकता है। कई मामलों में लीवर फेलियर के भी चांस होते हैं। इसलिए दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।

सुस्ती महसूस होना: इसके अलावा कई बार पैरासीटामॉल लेने के बाद बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होती है। तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरुर लें।

आंखों के दर्द से जुड़ी खास बातें

बहुत से लोग अपनी आंखों को लेकर बहुत ही लापरवाह होते हैं और आंख में हल्के-फुल्के दर्द या समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये आदत भारी पड़ सकती है और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं।

आंखों में दर्द के कारण

आंखे अनमोल हैं और शायद इसलिए ही ये शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग हैं। आंखे जितनी अनमोल हैं, इनको देखभाल की भी उतनी ही जरूरत होती है। बहुत से लोग अपनी आंखों को लेकर बहुत ही लापरवाह होते हैं, और आंख में हल्के-फुल्के दर्द या समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपकी ये आदत भारी पड़ सकती है। तो आंखों के दर्द को नज़रअंदाज न करें और जानें कि आंख में क्यों दर्द हो रहा है।

ऊपरी सतह पर दर्द

कई बार आपकी आंख की ऊपरी सतह पर दर्द होता है, और आपको इससे आंख में जलन, और खुजली भी महसूस होती है। यह अक्सर तब होता है जब आपको आंख में कोई चोट लगी हो। इस तरह का दर्द होने पर आप डाक्टर की सलाह पर आई ड्राप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

भीतरी भाग में दर्द

आंखों के भीतरी भाग में दर्द होने पर आप अपनी आंखों में स्पंदन और किरकिरेपन जैसा महसूस करते हैं। इस तरह की स्थिति तुरंत में डॉक्टर से मिले क्योंकि यह किसी गंभीर चोट की वजह से होने वाला दर्द हो सकता है।

गंदगी की वजह से होने वाला दर्द

धूल मिट्टी से होने वाले दर्द से आंखों में खुजली होती है और वे लाल हो जाती है। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आंखों पर ठंडे पानी की छिटे मार कर इन्हें धोएं। इससे आंखों की गंदगी साफ हो जाएगी। आंखों पर हाथ न लगाएं।

चोट की वजह से आंख में दर्द

चोट लगने पर आंखों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। आंखों में जलन या बहुत तेज दर्द होना, इसका सबसे पहला लक्षण होता है। यह बहुत तेज रोशनी या सूरज की किरणों से भी हो सकता है।

गुहेरी

यह आमतौर पर आंखों के अंदरुनी भाग के किनारों पर होती है। ये आंख में किसी फुंसी के हो जाने जैसा होता है। ऐसे में आंख बेहद संवेदनशील हो जाती है और इसकी वजह से थोड़ा दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके इलाज का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे छूएं नहीं, और अपने आप ठीक होने दें। बस आंख की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें।

कॉंटेक्ट लेंस के कारण

जब आप हर समय कांटेक्ट लेंस पहने रहते हैं और इसे समय-समय पर साफ नहीं करते हैं तो इससे आंखों में जलन होने लगती है और कभी-कभी दर्द भी होता है। पुराने या इक्स्पाइरी कांटेक्ट लेंस पहने से आपकी आंखों में संक्रमण भी हो सकता है।

ग्लूकोमा के कारण

ग्लूकोमा यानी काला मोतिया एक गंभीर नेत्र रोग होता है। यह धीमी गति से आंखों को हानि पहुंचने वाली बीमारी है, इससे आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है और यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है।

उम्मीद की किरण है गर्भ प्रत्यारोपण

गर्भ प्रत्यारोपण उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जो गर्भधारण नहीं कर सकती। इस तकनीक के जरिए दूसरी महिला का गर्भ प्रत्यारोपित करके गर्भधारण कराया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए वरदान की तरह है जो किसी बीमारी के कारण या गर्भ में समस्या के कारण मां बनने का सुख नहीं प्राप्त कर सकती हैं।

प्रत्यारोपण रहा सफल

गर्भ प्रत्यारोपण का प्रयास कई सालों से हो रहा है, लेकिन पहली बार सफलता प्राप्त की स्वीडन के चिकित्सकों ने। स्वीडन के डॉक्टरों ने अजूबा कर दिखाया। 36 साल की एक ऐसी महिला को मां बनने की खुशी दे दी, जिसके पास गर्भाशय ही नहीं था। यह मामला इसलिए भी खास है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्यारोपित गर्भाशय से जन्म लेने वाला बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।

पहले भी हुए प्रयास

इससे पहले भी गर्भाशय प्रत्यारोपण के जरिए कई प्रयास किए गए लेकिन कभी उन्हें शरीर ने स्वीकार नहीं किया तो उसे निकालना पड़ा तो कभी गर्भपात हो गया। 2000 में पहली बार सऊदी अरब में यूटरस ट्रांसप्लांट किया गया था। चार माह बाद ही महिला के शरीर ने ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया। आखिर उसे निकालना पड़ा। इसके बाद टर्की में कोशिश हुई। शरीर ने गर्भाशय तो स्वीकार कर लिया, लेकिन गर्भपात हो गया।

बच्चा है स्वस्थ

स्वीडन में पैदा हुआ बच्चा 1.8 किलो (3.9 पौंड) का है। प्रसव सिजेरियन के जरिए हुआ है। सात अन्य महिलाओं को भी इसी तरह यूटेरस ट्रांसप्लांट किए गए हैं। पांच अब भी गर्भवती हैं। डॉक्टर आशान्वित है कि जल्द ही और खुश-खबरें भी मिलेंगी।

समस्याएं भी आई

प्रत्यारोपित गर्भ से गर्भधारण के बीच में कई तरह की समस्याएं भी आईं। गर्भधारण के 31वें हफ्ते तक सबकुछ सामान्य रहा। इसके बाद महिला को हाई ब्लडप्रेशर से जुड़ी प्री-एक्लांपसिया बीमारी हो गई। बच्चे की हार्ट रेट भी असामान्य पाई गई। डॉक्टरों ने समय पूर्व डिलिवरी कराने का फैसला किया। लेकिन बाद में सबकुछ ठीक हो गया, लेकिन प्रसव सिजेरियन के जरिए हुआ।

महिला बीमारी से ग्रस्त थी

जिस महिला को गर्भ प्रत्यारोपण के बाद मां बनाया गया वह रॉकिटांस्की जेनेटिक सिंड्रोम से पीड़ित थी। 4500 में से किसी एक महिला को यह बीमारी होती है। महिला जब 15 साल की हुई तो पहली बार उसे इसका पता चला। महिला को उसकी 61 साल की पारिवारिक मित्र ने अपना यूटेरस दान किया। चिकित्सक तब हैरान रह गए जब 61 साल की इस महिला की कोख गर्भधारण के लिए टेस्ट में दुरुस्त पाई गई, जबकि सात साल पहले उसका मेनोपॉज बंद हो चुका था। यह उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण की तरह है जो किसी परेशानी के कारण मां बनने में सफल नहीं हो पाती है।

किशमिश खाकर करें वजन कम

सूखे मेवे के सेवन से भी वजन को घटाया जा सकता है। इसमें किशमिश का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए ये पढ़े। किशमिश को सूखे मेवे का राजा कहा जाता है। किशमिश का सेवन सीधे तौर पर वजन घटाने के लिए नहीं होता है लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। किशमिश को उसके पोषण तत्वों और स्वास्थ्य लाभों के कारण हीरा माना जाता है। किशमिश खाने से ब्लड बनता है, वायु, पित्त और कफ दोष दूर होता है।

एनर्जी देता है

किशमिश में मौजूद शर्करा शरीर में आसानी से पच जाती है। नतीजनत् शरीर को शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती है। किशमिश पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है। किशमिश में घुलनशील फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह घुलनशील फाइबर बुरे कोलेस्ट्रॉल का विरोध करता है। इसके अलावा किशमिश पोलीफेनोल्स एंजाइम को भी दबाता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित के लिए जिम्मेदार होता है।

पाचन को ठीक रखता है

रोजाना किशमिश का सेवन करने से आपका हाजमा ठीक रहता है और पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करता है। किशमिश लैक्सटिव के रूप में कार्य करती है। यह पेट में जाकर पानी को अवशोषित करती है, जिसके फलस्वरूप कब्ज से राहत मिलती है। किशमिश में पाये जाने वाले फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मार्ग से विषाक्त और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

हड्डियों को मजबूत करता है

मोटे लोगो की हड्डियां कमजोर होती है। शरीर का ज्यादा वजन भी हड्डियों को कमजोर और दुर्बल बनाता है। अगर आप वजन कम कर रहे हो तो सारे आहार वजन कम करने वाले नहीं लेने चाहिए, ये तरीका आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको कुछ ऐसे आहार शामिल करने चाहिए जो आपको ऊर्जा दे सके। इसके लिए किशमिश सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आप शक्कर बिल्कुल भी नहीं लेते हो तो भी किशमिश आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखती है। किशमिश कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

स्वस्थ रखता है

एक फिट व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किशमिश सीधे तौर पर भले ही वजन कम करने में सहायक ना हो, लेकिन इससे मिलने वाले फासदे वजन को नियंत्रित करने में मदद करते है।

उदाहरण के तौर पर रोजाना किशमिश खाने वाले व्यक्ति को हृदय से जुड़ी परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। किशमिश आपके शरीर में पीएच स्तर को भी संतुलित रखता है। आवश्यक मात्रा में किशमिश का सेवन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है।

रेसिपी

आलू कुरकुरे

सामग्री

1 कप उबले , छिले और मसले हुए आलू, 1/2 कप कटा हुआ पुदीना, 12 टेबल-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टी-स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी-स्पून नींबू का रस, नमक स्वादअनुसार, 5 टेबल-स्पून मैदा, 5 टेबल-स्पून पोहा , दरदरा क्रश किया हुआ, तेल,
परोसने के लिए: स्वीट एण्ड सॉर सॉस

विधि

आलू, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नींबू का रस और नमक को एक बाउल में अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को 6 बराबर भाग में बांटकर, प्रत्येक भाग के छोटे गोले बना लें। एक तरफ रखें। मैदा को थोड़े पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा और मुलायम पेस्ट बनाकर एक तरफ रख दें। प्रत्येक आलू के बॉल को मैदा के पेस्ट में डुबोकर पोहे में अच्छी तरह से लपेट लें। एक गहरी कढ़ाई में तेल गरम करें, थोड़े-थोड़े आलू बॉल डालकर उनके सभी तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज़ पर निकाल लें। स्वीट एण्ड सॉर सॉस के साथ गरमा गरम परोसें।

कॉर्न एंड वेजिटेबल रोटी

सामग्री

1 कप मकई का आटा, 1/2 कप कसी हुई फूलगोभी, 1/2 कप बारीक कटी हुई मेथी, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 कप उबले , छिले और कसे हुए आलू, 2 टी-स्पून तेल, 1 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक सवादअनुसार, मकई का आटा , तेल
परोसने के लिए: ताज़ा दही, अचार

विधि

मकई के आटे को छानकर, सभी सामग्री मिलाकर, ज़रुरत हो उतना गुनगुना पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। आटे को 7 बराबर भाग में बांटकर, प्रत्येक भाग को थोड़े सूखे मकई के आटे का प्रयोग कर 125 एमएम। (5) व्यास के गोल आकार में बेल लें। एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और थोड़े तेल का प्रयोग कर प्रत्येक रोटी को दोनो तरफ सुनहरे दाग पड़ने तक पका लें। ताज़े दही और अचार के साथ तुरंत परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**